● वर्ष-3
● अंक-291
रायपुर, मंगलवार
16 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› क्या हिंदू धर्म में है 33 करोड़ देवी-देवता

बॉर्डर पुलिस को मुख्यमंत्री हिमंत का निर्देश

हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरणों के पास न भेजें

गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य की सीमा पुलिस को निर्देश दिया है कि 2014 के अंत से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई लोगों के नागरिकता मामलों को सीधे विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजा जाए। इसके बजाय, सीमा पुलिस को उन्हें नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। सीएए असम की ब्रह्मपुत्र घाटी सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन को उकसाया था, लेकिन राज्य की मुख्य रूप से बंगाली भाषी बराक घाटी में इसका स्वागत किया गया था, अंततः इस साल मार्च में इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों की अधिसूचना के साथ गति में आ गया। सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। हालांकि, असम बांग्लादेश से एक लंबी सीमा साझा करता है और जहां पड़ोसी देश से अवैध आप्रवासन का सवाल लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, 24 मार्च, 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को घोषित करने की अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद से चार महीनों में राज्य से केवल आठ लोगों ने सीएए के विशेष प्रावधानों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन आठ में से केवल दो ही प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं।

5 जुलाई को सम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग ने असम पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक (सीमा) को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि सीएए के प्रावधानों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों को विदेशी न्यायाधिकरणों के पास नहीं भेजा जाएगा और ऐसे लोगों की एक विशेष रजिस्ट्री रखी जाए।

असम में सीएए के तहत आठ आवेदन : शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को बताया कि राज्य से अब तक केवल आठ लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है। शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुएबताया कि इन आवेदकों में से केवल दो ही व्यक्तियों ने संबंधित अधिकारियों को साक्षात्कार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की बराक घाटी में इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई हिंदू बंगाली परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया. लेकिन उन्होंने आवेदन करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण (एफटी) में अपना मामला लड़ना पसंद करेंगे। विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण असम के लिए विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक निकाय है जो बाहर से आए लोगों राष्ट्रीयता के मुद्दे पर विचार करता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किए गए अधिकतर हिंदू-बंगाली परिवारों ने उन्हें बताया कि उनके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, लेकिन वे सीएए के जरिए आवेदन करने के बजाय एफटी को प्राथमिकता देते है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यदि विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी करार दिए गए लोगों की राष्ट्रीयता पर प्रतिकूल फैसला आता है तो वे बाद में सीएए के तहत आवेदन कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, जब नागरिकता के लिए मामला चल रहा है तो नए कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

सीजीपीएससी मामले की जांच से शंका होगी दूर-रमन

भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

रायपुर। भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से छत्तीसगढ़ की सुख शांति के लिए हम यहां उपस्थित हुए है. इस दौरान उन्होंने सीजीपीएससी मामले में जांच को लेकर कहा कि उच्च स्तरीय जांच से युवाओं के मन की शंका दूर होगी. कार्यक्रम में शामिल होने जगन्नाथ मंदिर पहुंचे डॉ. सिंह ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का अपनी मौसी के यहां से निवास स्थान पर वापसी को लेकर पूरे देश में उत्साह है. पूरे देश में जहां जगन्नाथ मंदिर है वहा लोगों की आस्था जुड़ी है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि और विकास की गंगा बहती रहे. वहीं इस दौरान सीजीपीएससी मामले में शुरू हुई जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा की सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है. इस मामले में सरकार की ओर से जांच की रिक्वेस्ट की गई थी. मामले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के खास तौर पर युवाओं में पीड़ा थी, युवा वह उदवलित थे. इसके लिए लोगों ने जांच की मांग की थी. डॉ. सिंह ने कहा कि इस उच्च स्तरीय जांच से छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के मन की शंका दूर होगी. एक नया रास्ता बनेगा ताकि इस तरीके का करप्शन देश में कहीं न हो, छत्तीसगढ़ में तो इस तरह का करप्शन होना भी नहीं चाहिए.

कांग्रेस ने की मानसून सत्र बढ़ाने की मांग-चरणदास महंत- 26 जुलाई तक चलेगा. इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मानसून सत्र के लिए 5 दिनों के समय को नाकाफी बताते हुए तारीख बढ़ाने की मांग की है. इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने सवाल किया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मानसून सत्र के लिए 5 दिन का समय हमें छोटा लग रहा है. जब सत्ताधारी पार्टी विपक्ष में थी तो उन्हें 5 दिन का समय छोटा लगता है. बता दें कि बलौदाबाजार आगजनी, खाद-बीज, कानून अव्यवस्था के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी व प्रदेशभर के कार्यकर्ता 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे. इस बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून की स्थिति बिगड़ गई है. दिन दहाड़े डकैती, चोरी, गोलीबारी और रेप जैसे मामले सामने आ रहे है. हम इन मुद्दों को सामने लेकर आएंगे और सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखेंगे. सीजीपीएससी मामले में सीबीआई की जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जयेगा। इसके बाद सब संतुष्ट हो जाएंगे.

अपने साथ बारिश लेकर आए है भगवान- भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम यहां विधानसभा अध्यक्ष (डॉ रमन सिंह) के साथ मौजूद है. आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा यहां वापस पहुंच रही है, इसलिए पुरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करने हम आए है.

बढ़ते दामों के बीच राहत: 20 से भी ज्यादा दिन सुरक्षित रख पाएंगे इन किस्मों के टमाटर

नई दिल्ली। देश में इन दिनों टमाटर की कीमतें आसमान पर हैं। कहीं 100 तो कहीं 80 रुपये प्रति किलो तक टमाटर बिक रहा है। इस बीच, आईसीएआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने बेंगलुरू स्थित संस्थान में टमाटर की दो ऐसी संकर प्रजाति विकसित कर रहा है जो भविष्य में संकट से बचा सकता है। आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह को लेकर सोमवार को पूसा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने बताया कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) द्वारा विकसित की गई संकर टमाटर की किस्में, अर्का रक्षक और अर्का अबेध ऐसी हो किस्म हैं, जो तीन सप्ताह से भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सकती हैं। हमें इन किस्मों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने की जरूरत है। इससे भविष्य में बढ़ती कीमतों पर भी लगाम लग सकती है। आईआईएचआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक चन्द्रशेखर सी के अनुसार, 2012 में विकसित भारत का पहला ट्रिपल रोग प्रतिरोधी टमाटर एफ1 हाइब्रिड अर्का रक्षक की खेती वर्तमान में 7,000 हेक्टेयर में की जाती है। इस हाइब्रिड तकनीक का लाइसेंस 11 कंपनियों को दिया गया है। 2012-22 के दौरान बीज बिक्री से 3,600 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। वहीं, तीन साल विकसित की गई टमाटर की अर्का अबेध किस्म तीन सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती है। यह दूर के बाजारों के लिए उपयुक्त है। उन्होंने ये भी बताया कि टमाटर की ये दोनों किस्में लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट सहित कई बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती हैं। महानिदेशक हिमांशु पाठक ने कहा कि 100 दिन में नई बीज किस्में और नई तकनीक के साथ संस्थान एक नई पहल की शुरुआत करेगा। इसमें खेत स्तर पर उच्च उपज वाली बीच किस्म बीज हब की स्थापना के साथ-साथ जिलों में तिलहन और दालों के लिए विशिष्ट केंद्र शामिल है।

प्रमुख समाचार

तेलंगाना में दो लाख रुपये तक के फसल ऋण की माफी

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को कहा कि उसके द्वारा घोषित की गयी एक नीति के मुताबिक दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 12 दिसंबर, 2018 को या उसके बाद दिये गये या नवीनीकृत किये गये ऐसे फसल ऋण को माफ कर दिया जाएगा जिसे नौ दिसंबर, 2023 तक चुकाना था। सरकार ने ऋणमाफी के दिशानिर्देशों पर सोमवार को तेलुगू में आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि किसान परिवारों की पहचान के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के पीडीएस कार्ड के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवार में उसके मुखिया, उनकी जीवन संगिनी, बच्चे एवं अन्य शामिल होंगे। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इस योजना में आईटी साझेदार के रूप में काम करेगा। दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी राज्य कृषि विभाग के निदेशक एवं एनआईसी के बीच समन्वयन का काम करेंगे।

सुको ने खारिज की हिंडनबर्ग मामले पर पुर्नविचार याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच विशेष जांच दल या सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने 5 मई के अपने आदेश में कहा था कि समीक्षा याचिका का अध्ययन करने के बाद, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है। समीक्षा याचिका पर न्यायाधीशों ने चैंबर में विचार किया। अडानी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में शीर्ष अदालत ने 3 जनवरी को सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया।

अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, टली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी। उच्च न्यायालय ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके द्वारा केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, जो याचिका पर सुनवाई करने वाली थीं, को केजरीवाल के वकील ने सूचित किया कि ईडी ने उन्हें रविवार देर रात ही अपने प्रत्युत्तर की एक प्रति दी थी और उन्हें इसका जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और वे आदेश की प्रति रिकॉर्ड में रखेंगे। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। 20 जून को केजरीवाल को यहां एक ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

दिलजीत दोसांझ के साथ पोस्ट को लेकर घिरे कनाडाई पीएम

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के साथ पोस्ट को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर करारा हमला बोला है। पोस्ट में ट्रूडो ने अभिनेता की प्रशंसा तो की, लेकिन भारत के बजाय केवल पंजाब से उनके जुड़ाव का जिक्र किया। दरअसल, रविवार को कनाडा के ओंटारियो के डाउनटाउन टोरंटो के रोजर्स सेंटर स्टेडियम में दिलजीत की परफॉर्मेंस से पहले पीएम ट्रूडो अचानक उनसे मिलने पहुंचे। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूडो ने दिलजीत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कनाडा एक महान देश है, जहां पंजाब का एक लड़का इतिहास बना सकता है और स्टेडियमों को भर सकता है। कनाडा के पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा कि रोजर्स सेंटर में रुककर दिलजीत को उनके शो से पहले शुभकामनाएं दीं। विविधता सिर्फ हमारी ताकत नहीं है। यह एक महाशक्ति है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्रूडो पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

मुहर्रम पर अमेठी में लगे विवादित नारे, एक्शन में योगी

नई दिल्ली। राजनीति के केंद्र में रहने वाला अमेठी एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि, इस बार राजनीति और चुनाव लड़ाई को लेकर नहीं, बल्कि विवादित नारे की वजह से है। दरअसल, गांधी परिवार और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में मोहर्रम जुलूस के दौरान विवादित नारे लगने से अमेठी का माहौल गर्मा गया है। मुहर्रम के जुलूस में युवकों द्वारा लगाए गए भड़काऊ नारे से हड़कंप मचा है। जुलूस के दौरान युवकों ने हिंदुस्तान में रहना है, या हुसैन कहना है के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने एक बयान में कहा, मुसाफिरखाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में लाया गया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जनगणना इसलिए जरूरी है

बेहतर और कल्याणकारी नीतियां बन सकें, आबादी की सटीक जानकारी मिल सके

पत्रलेखा चटर्जी

हम वर्ष 2024 का आधा पड़ाव? पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी कर चुकी है। लेकिन हर दस वर्ष में होने वाली जनगणना को लेकर अब तक कोई बात नहीं की जा रही। अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। भारत ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी जनगणना करवाई थी, लेकिन 1981 से हर दस वर्ष में शुरू हुए जनगणना के क्रम को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि चार साल बीत जाने के बावजूद हमारे पास अब भी जनगणना कराने के लिए समय नहीं है। बांग्लादेश और ब्राजील ने अपनी अंतिम जनगणना 2022 में संपन्न कराई थी। अमेरिका और चीन, तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जनगणना 2020 में ही करवा चुके हैं। जनगणना के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक देश के लोगों की संख्या और जनसांख्यिकीय व सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं की जानकारियां बड़े स्तर पर जुटाई जाती हैं।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ऐंड डेवलपमेंट, केरल?से संबंधित दो प्रतिष्ठित जनसांख्यिकीविद एस. इरुदया राजन और यूएस मिश्रा ने हाल ही में टिप्पणी की, कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में जनसंख्या की गणना वास्तविक नहीं है। दरअसल, भारत की जनसंख्या के ज्यादातर अनुमान दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत जब तक अपनी समुचित जनगणना नहीं करा लेता, तब तक हमारे पास सिर्फ अनुमान ही होंगे।

जनगणना में देरी के पीछे जो भी कारण हों, लेकिन जनगणना के आंकड़ों की कमी एक गंभीर मसला है। यह न केवल शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जनगणना के आंकड़ों में देरी की वजह से कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होता है। जैसा राजन और मिश्रा भी इंगित करते हैं कि 'सटीक जनसंख्या और जनसांख्यिकीय संरचना को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बेहतर नीतियों का मसौदा तैयार कर सकें।'

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के अंतर्गत?देश के करीब 81.35 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर, 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यह राशन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिया जा रहा है। सरकार?के?2019 के बयान के आधार पर देश की 67 फीसदी आबादी यानी 80 करोड़?लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के हकदार हैं। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मौजूदा समय में करीब 92 करोड़ लोग इस दायरे में आने चाहिए। अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े मिलने पर एनएफएसए को लाभ मिलेगा। यह बात उन अज्ञात लाभार्थियों पर भी लागू होती है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित हैं।

जनगणना के नवीनतम आंकड़े नहीं होने की कई चुनौतियां हैं। एक शोधकर्ता का कहना है कि यदि हमें बच्चों का टीकाकरण करना है, आंगनवाड़ी कहां खोलनी है या पीडीएस में कितने परिवारों को शामिल करना है, तो इसके लिए जनगणना की जरूरत है। यही जनसंख्या के आंकड़ों का एकमात्र स्वतंत्र स्रोत है, जिससे प्रशासन और गांव स्तर तक आबादी की विशेषताओं, जैसे-आयु, लिंग, परिवार का आकार आदि की जानकारी मिलती है। कई शोधकर्ताओं ने इस ओर ध्यान दिया है कि प्रशासनिक आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकारी तंत्र किन लोगों तक पहुंच पाया। ऐसे में, पक्षपात की आशंका बनी रहती है। यह तथ्य जननीति के लिए स्वतंत्र और पूर्ण जनगणना की मांग को स्पष्ट करता है।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों ने हाल के वर्षों में कोई देशव्यापी सर्वे नहीं किया है। इनमें 2022-23 का वार्षिक?आवधिक?श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस/एमपीसीई), 2020 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का वार्षिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21 का एनएफएचएस-5) किए गए हैं। लेकिन जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के बिना यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। उम्मीद है कि नई गठबंधन सरकार इस ओर ध्यान देगी।

आदिवासी सरपंच को हटाकर सामान्य वर्ग से बना अध्यक्ष

■ जनकपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने का है मामला

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भरतपुर विकासखंड के जनकपुर ग्राम पंचायत के नगर पंचायत में बदलने के बाद यहां सरपंच को भी बदल दिया गया।यहां पर आदिवासी महिला सरपंच को हटाकर सामान्य वर्ग के अशोक सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। जिसे लेकिन अब विवाद शुरु हो गया है एमसीबी जिले में बीजेपी उपाध्यक्ष और भरतपुर जनपद उपाध्यक्ष दुर्गाशंकर मिश्रा ने इस हरकर पर आपत्ति जताई है। उपाध्यक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को पत्र लिखकर आदिवासी महिला को अध्यक्ष बनाने की मांग की है।

बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दुर्गाशंकर मिश्रा ने पत्र के जरिए कहा कि नगर पंचायत जनकपुर, जनपद पंचायत भरतपुर, जिला एमसीबी में नगर पंचायत की घोषणा के आधार पर ग्राम पंचायत को भंग करते हुए जनकपुर नगर पंचायत की समिति का गठन किया गया। जिसमें अशोक सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है।जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं। जबकि ग्राम पंचायत जनकपुर आदिवासी महिला पद के लिए आरक्षित है।उसमें आदिवासी महिला को ही अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। क्योंकि नगर पंचायत जनकपुर के अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं हुआ है।इस आधार पर सामान्य वर्ग का अध्यक्ष बना दिया गया है। जिसमें नियम का उल्लघंन हुआ है।

दुर्गाशंकर मिश्रा के मुताबिक जिलाध्यक्ष बीजेपी अनिल केशरवानी ने मनमाने ढंग से अध्यक्ष और सदस्यों को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के यहां जो सूची भेजी थी, वो गलत है। जिला अध्यक्ष एमसीबी और जिला संगठन के पदाधिकारियों के अलावा मण्डल जनकपुर के पदाधिकारियों की परमिशन नहीं ली गई है । बिना किसी परमिशन के ही महिला आदिवासी आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग के पुरूष को अध्यक्ष बना दिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन आदिवासियों पर विशेष सहानुभूति रखती है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दुर्गाशंकर मिश्रा ने पत्र में निवेदन किया है कि समिति का अध्यक्ष पद किसी महिला आदिवासी को दिया जाना चाहिए जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के आदिवासियों को न्याय मिल सकें।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा सरपंच का कहना है हम लोग के साथ कूटनीति के तरीके से राजनीति की गई है। जो कभी निर्वाचित नहीं हुआ है उसको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे आदिवासी लोगों के साथ शोषण किया गया है।अनिल केशरवानी जिलाध्यक्ष हैं उनको सभी लोगों के सामने बात को रखकर सहमति बनानी चाहिए। मैं सामान्य अध्यक्ष बनने से दुखी नहीं हूं।लेकिन आदिवासियों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा।

वहीं नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक सिहं ने कहा कि जो दायित्व उन्हें दिया गया है वो उसे बखूबी निभाएंगे।

नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा हमारी वर्तमान विधायक रेणुका दीदी से दायित्व मुझे मिला हुआ है कि जनकपुर को अच्छे ढंग से सजाया जाए। यहां के लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। उस दिशा में हम सब को मिलकर जनकपुर के नगरवासियों के सभी के सहयोग से अच्छा से अच्छा काम करना है। वहीं जनकपुर ग्राम पंचायत के सरपंच ने इस बारे में आपत्ति जताई है।

जमुनिया बाई ने कहा सब पंच सरपंच लोग को निकाल कर बाहर कर दिए हैं। दूसरे लोग अध्यक्ष सचिव बन गए हैं। हम लोग के साथ अन्याय किए हैं। हम लोग का चार माह का कार्यकाल बचा है। चार महीने हम लोग को नगर पंचायत में रहने देते। आगे जो होता तो होता शासन प्रशासन हम लोग के साथ अन्याय किए हैं। आदिवासी महिला सरपंच की माने तो उनके साथ धोखा किया गया है। अब महिला सरपंच और पंच न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही अब नए नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर असंतोष की भावना बढ़ती दिख रही है।

शहर के स्कूल में घुसा हाथी, घंटों मशक्कत के बाद खदेड़ा गया

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में एक हाथी रविवार को घुस आया। इससे अफरा-तफरी मच गई। हाथी ने पक्की तालाब में स्थित कृष्ण कुंज में लगी जाली को हटा दिया। इसके बाद पास में ही स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के गेट को तोड़ दिया। गेट तोडऩे की घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में नजर आया कि हाथी पहले गेट की ओर बढ़ता है गेट को बंद देख वापस लौटता है। इसके बाद फिर वहीं लौटता है। तभी हाथी पर नजर बनाए हुए व मुनादी के माध्यम से नगरवासियों को सचेत कर रहे वन विभाग व हाथी मित्र दल वाहन के जरिए गेट के सामने स्थित मुख्य मार्ग पर पहुंचते हैं। वाहन में लगे तेज आवाज वाले सायरन को बजाते हैं। सायरन की आवाज से हाथी घबरा जाता है और वहां से भागने के लिए तेज गति के साथ फिर से स्कूल के गेट की ओर बढ़ता है और इस बार गेट को तोड़ते हुए स्कूल के परिसर में प्रवेश कर जाता है। स्कूल परिसर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वहां से वापस लौट कदमपारा चौक के पास बसे रिहाईशी इलाके की ओर बढऩे लगता है। इधर वन विभाग की टीम व हाथी मित्र दल हाथी को खदेडऩे के प्रयास में लगातार लगे हुए थे। कई घंटों के प्रयास के बाद वन विभाग व हाथी मित्र दल ने हाथी को नगर से बाहर खदेड़ा तो वह नए बस स्टैंड के पीछे मौजूद जंगल में चला गया।

पीएम स्वनिधि योजना का बेहतर क्रियान्वयन

■ बिलासपुर नगर निगम को मिलेगा 'सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग 2023-24' पुरस्कार

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम ने एक बार फिर देश में अपना परचम लहराया है। पंडित दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन की पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और असाधारण प्रदर्शन के लिए बिलासपुर नगर पालिक निगम को सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटकल रियल टाईम रैकिंग स्पार्क 2023-24 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली में दिया जाएगा। जिसमें केंद्रीय शहरी आवासन मंत्री मनोहरलाल खट्टर और केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहेंगे।

पीएम स्वनिधि याने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स निधि, जिसका एकमात्र उद्देश्य सड़क किनारे व्यापार करने वाले, रेहड़ी व्यापारी और लघु व्यापारियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10 हजार से लेकर 50 हजार तक का ऋण स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यापार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है।

बता दें, कि 1 जनवरी 2024 से 12 जुलाई 2024 तक पीएम स्वनिधि के प्रथम ऋण 10 हजार, द्वितीय ऋण 20 हजार और तृतीय ऋण के लिए 330 कुल 12126 आवेदन का लक्ष्य मिला था। इसमें अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए नगर निगम ने प्रथम ऋण में 15534, द्वितीय में 5411 और तृतीय में 597 कुल मिलाकर 21542 आवेदन प्राप्त किए और स्वीकृत तथा पात्र आवेदनों पर तेज गति से कार्य करते हुए रिकार्ड समय सीमा में प्रथम श्रेणी के 7079, द्वितीय श्रेणी के 2009 और तृतीय श्रेणी के 377 कुल मिलाकर 9465 हितग्राहियों को प्रक्रिया पूरी करते हुए ऋण का आबंटन भी कर दिया।

शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से 80 लाख की ठगी

बिलासपुर। शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से 80 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलाने का झांसा देकर रिटायर्ड कर्मचारी को लाखों का चुना लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला बाजपेयी कैसल निवासी शिक्षा विभाग केरिटायर्ड कर्मचारी विरेन्द्र कुमार देवांगन साइबर थाने में शिकायत की है कि 2 मई 2023 की सुबह उनके मोबाइल में दो अनजान मोबाइल नम्बर से फोन आया। जिसमें फोन करने वाले ने उन्हें खुद को मैस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैदराबाद का सीईओ व मैनेजर बताते हुए कहा आपने इस बीमा कंपनी में इन्वेस्ट किया है।

97926 हितग्राहियों को किया जा रहा है छः प्रकार की पेंशन से लाभान्वित

महासमुंद। महासमुंद जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और उनका नियमानुसार क्रियान्वयन के लिए सजग है। समाज कल्याण की विभिन्न विभागीय योजानाओं के तहत् महासमुंद जिले में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में 97 हजार 926 हितग्राहियों को छः प्रकार की पेंशनों से लाभान्वित किया जा रहा है। समाज् कल्याण विभाग की उपसंचालक श्रीमती संगीता सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 60-79 वर्ष आयु वर्ग के 30172 एवं 80 वर्ष के आयु वर्ग के 3998 इस प्रकार 34170 वृद्धावस्था व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। वही इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत् 9932 विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है। जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।

इंदिरा गांधी निःशक्तजन (दिव्यांग) पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 987 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 24 हजार 874, सुखद सहारा योजना के तहत् 9216 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 18747 पात्र हितग्राहियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे व्यक्तियों जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, निराश्रित वृद्ध या 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेश में निश्शक्त व्यक्तियों की पहचान से लेकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालीन अनुभवों तथा उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (एक अक्टूबर) को सम्मानित किया जाता है।

पुलिस कर्मी का ट्रक ड्राइवर से पैसे लेते वीडियो वायरल

बलरामपुर। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी खुलेआम पैसे लेता नजर आ रहा है। इस वीडियो को ग्रामीणों ने सोशल मीडिया में वायरल किया है। मामले में एएसपी ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला रामानुजगंज के तातापानी पुलिस चौकी का है। यहां एक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी ट्रक ड्राइवर से पैसे लेता नजर आ रहा है।

दुर्ग जिला अस्पताल की डॉक्टर विनीता धुर्वे ने 101 जुड़वां बच्चों की डिलीवरी कर बनाया रिकॉर्ड

दुर्ग। दुर्ग जिला अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट में पदस्थ डॉ. विनीता धुर्वे ने महज ढाई साल में 101 जुड़वां बच्चों की डिलीवरी कराकर देश में एक रिकॉर्ड दर्ज कराया है। डॉ विनीता धुर्वे अब तक 14 हजार 500 प्रसव करा चुकी हैं। वे देश की पहली डॉक्टर हैं, जिन्होंने जुड़वां बच्चों की डिलीवरी कराने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है।

दरअसल, दुर्ग जिला अस्पताल की डॉ। विनीता ने शुक्रवार को फिर दो जुड़वां बच्चियों की डिलीवरी कराई है। ये उनकी जुड़वां बच्चों की 101वीं डिलीवरी थी। भिलाई के कैलाश नगर निवासी शेख फैयाज की पत्नी बुशरा परवीन ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है। खास बात ये है कि उन्होंने इस दौरान सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराई है। वहीं 6,480 प्रसव सीजेरियन ऑपरेशन से करा चुकी हैं।

इस बारे में डॉ। विनीता धुर्वे ने बताया, 2011 से लगातार मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी करा रही थीं, लेकिन काउंटिंग करने में कभी ध्यान नहीं दिया। 2022 से 2024 के बीच 100वें जुड़वां बच्चों की डिलीवरी कराकर शतक का रिकॉर्ड बनाया है। मेरी इस उपलब्धि में मेरे स्टाफ का भी पूरा सहयोग मिला। इसी वजह से यह रिकॉर्ड बन पाया है। कभी भी जुड़वां बच्चों की डिलीवरी का केस आता है तो स्टाफ के सभी डॉक्टर उनके पास ही रहते हैं।

बता दें कि डॉ। विनीता धुर्वे ने साल 2003 में रायपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद दुर्ग में ही इंटर्नशिप की। इसके बाद दुर्ग जिले के रसमड़ा, अहिवारा सहित अलग-अलग जगहों पर पदस्थ रही। साल 2011 से दुर्ग जिला अस्पताल के मैटरनिटी वॉर्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव में पुलिस बल को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस जवान मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों के ठिकानों पर कूच करने की तैयारी में निकल चुके थे। नक्सलियों को इस बात की खबर मिलते ही वे सारा सामान वहीं छोड़ कर नौ-दो-ग्यारह हो गए। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामाग्री जब्त की है। जानकारी के अनुसार, कोंडागांव पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को नक्सलियों के कैम्प का पुलिस टीम ने ग्राम उसेली, जबकसा, अडेंगा, डुवाल और आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना प्राप्त की थी। जब टीम नक्सलियों के कैम्प के पास पहुंची, तो पुलिस के आने से पहले ही नक्सली अपना कैम्प छोड़कर भाग चुके थे। इस ऑपरेशन में, पुलिस ने नक्सलियों के कैम्प से भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की। इसमें प्रेषर कुकर, अमुनियम नाइट्रेट, मेल फिमेल इलेक्ट्रानिक प्लग, अईईडी स्वी, तीर बम और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थी।

आयुष्मान कार्ड के मरीजों से जमकर वसूली

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिले के कई अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के अलावा मरीजों से रूपए की जमकर वसूली की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद विभाग ने जिले के आरबी हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्री मंगला हॉस्पिटल को नोटिस थमाया गया है। वहीं ओमकार हॉस्पिटल पर 1 लाख 82 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें, मरीजों का निःशुल्क इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत लगभग सभी बीमारियों का मरीज निःशुल्क सरकारी अस्पताल और पंजीकृत निजी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते है। और सरकार पैकेज के अनुसार इन अस्पतालों को भुगतान करती है। लेकिन जिले के कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड के अलावा मरीजों को अतिरिक्त रकम की वसूली कर रहे है। मरीजों की तरफ से इसे लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के अलावा और भी रुपए देने होंगे।

जांजगीर चांपा में दोस्तों के साथ नहाने गया युवक डूबा

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम देवरी पिकनिक स्पॉट में हसदेव नदी में नहाने के दौरान युवक आसुराम यादव 22 वर्ष तेज बहाव में बह गया। अपने 6 दोस्तों के साथ बिलासपुर से आया हुआ था। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खोजबीन की जा रही है। घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी अनुसार, रविवार को युवक आसुराम यादव अपने 6 दोस्तों के साथ बिलासपुर जिले से जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। रविवार की शाम करीबन 5.30 बजे हसदेव नदी में सभी दोस्त नहा रहे थे। तभी युवक आसूराम यादव नदी के तेज बहाव में बहने लगा। जिसे देख उसके दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहां पर युवक डूबा हुआ है। वह जगह 25 से 30 फिट गहरी है। कई लोगों की भी मौत उसी जगह हो चुकी है। जिला प्रशासन ने उस जहा में डेंजर जोन भी लिखा है। मगर लोग उसे मानने की वजह नदी में उतरकर मस्ती करते है।

जगदलपुर में तेज रफ्तार कार टकराई पुल से, पांच घायल

जगदलपुर। जगदलपुर के परपा थाना इलाके के ग्राम तोकापाल के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पुल से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों को चोट आई, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कार में पांच लोग सवार थे, जो कि दंतेवाड़ा एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, शादी कार्यक्रम से देर रात करीब एक बजे के लगभग अपनी कार से जगदलपुर के लिए निकले थे। सुबह जैसे ही तीन से चार बजे के बीच तोकापाल के पास पहुंचे कि अचानक कार चला रहे युवक को कुछ समझ नहीं आया और कार पुल से जा टकराई, इस घटना में कार सवार महिला का पैर फैक्चर हो गया, जबकि अन्य लोगों को भी चोट आई, घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया, जहां चिकित्सको ने उन्हें भर्ती कर दिया है।

अज्ञात वाहन की चपेट में आया जेल पहरी

जगदलपुर। नगरनार थाना क्षेत्र के ग्राम मारकेल में बीती रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जेल पहरी को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। रात ज्यादा होने के कारण लगातार बारिश के चलते कोई मृतक को देख नहीं पाया। सुबह लोगों के देखने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। जहां शव को पीएम के लिए मेकाज लाया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही जेल पुलिस हॉस्पिटल आ पहुंची। जहां शव का पीएम कराने में जुट गई है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए नगरनार पुलिस ने बताया कि सुबह जानकारी मिली कि मारकेल के पास एक युवक का शव देखा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर एक क्षतिग्रस्त बाइक भी बरामद किया है। इसके अलावा जेल पहरी इनेश बक्श 52 वर्ष का शव भी बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए मेकाज भिजवाया। वहीं जेल विभाग को सूचित किया गया। जेल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि इनेश बक्श मारकेल क्यों गया था।

कांग्रेस विधायक अश्लील एमएमएस कांड, फिर चढ़ा सियासी पारा

■ देवेंद्र यादव ने दर्ज कराया बयान

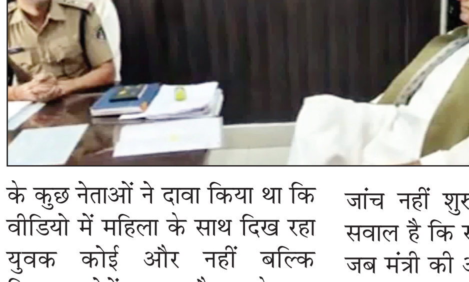

भिलाई। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव एमएमएस कांड मामले को लेकर भिलाई नगर थाने पहुंचे। जहां भिलाई नगर टीआई राजकुमार लहरे और सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने देवेंद्र यादव का बयान दर्ज किया है।करीबन एक घंटे तक टीआई के केबिन देवेंद्र यादव से पूछताछ की गई।इसके बाद देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र यादव की माने तो उन्होंने कथित वीडियो को फॉरेंसिक जांच करवाई है,जिसमें इसे टेंपर्ड वीडियो माना गया है।

आपको बता दें कि अश्लील वायरल एमएमएस को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया था कि वीडियो में महिला के साथ दिख रहा युवक कोई और नहीं बल्कि विधायक देवेंद्र यादव है। इसके बाद विधायक देवेंद्र यादव ने रोते हुए सफाई दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्ष के लोगों ने उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी एमएमएस जारी किया है।

देवेंद्र यादव ने कहा मैंने इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।ताकि वो इस मामले कि निष्पक्ष जांच करा सकें।लेकिन जांच नहीं शुरु हुई।गृहमंत्री से मेरा सवाल है कि रमन सिंह के शासन में जब मंत्री की अश्लील सीडी वायरल हुई थी तो सीबीआई जांच कराई गई थी।अब जब विधायक के साथ ऐसा हुआ है तो दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा।

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भी दावा किया था कि एमएमएस में दिख रहा व्यक्ति कोई और है। उन्होंने कहा था कि वह एमएमएस चार महीने पहले उनके पास आया था। इसको लेकर उन्होंने भिलाई नगर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उस एमएमएस की जांच भी कराई, जिसमें यह बताया गया कि एमएमएस में दिख रहा व्यक्ति देवेंद्र यादव नहीं है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के एमएमएस का मामला बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया था। चंद्राकर ने गृहमंत्री विजय शर्मा से मामले से जुड़ी एफआईआर की जांच की जानकारी भी मांगी थी। अब इसी मामले में भिलाई नगर पुलिस देवेंद्र यादव का बयान दर्ज किया जा रहा है।

छात्रावास में विशेष संरक्षित जनजातियों की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला

जांच टीम पर समाज के पदाधिकारी ने लगाया गंभीर आरोप

बलरामपुर। जिले के सनवाल स्थित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में विशेष संरक्षित जनजातियों की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था। शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। लेकिन अब वो टीम विवादों में आ गई है। जांच करने गए टीम पर पंडो समाज के पदाधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

बता दें कि सनवाल के प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की अधीक्षिका नीलिमा खलखो के द्वारा छात्रावास के बच्चियों को प्रताड़ित और दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था। जिस पर जिला प्रशासन ने टीम का गठन कर जांच करने की बात कही थी। वहीं जांच दल कन्या छात्रावास पहुंची और जांच भी किया। लेकिन पंडों समाज ने जांच दल पर आरोप लगाते हुए संभागीय कमिश्नर को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि लगभग 32 छात्राओं ने शिकायत की थी जबकि जांच टीम ने केवल 10 छात्राओं का ही कथन लिया। प्रताड़ना से तंग आकर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्रा का भी बयान दर्ज नहीं किया गया। संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि जो नए बच्चियों का छात्रावास में आगमन हुआ है, वे वहां के लिए अभी नए-नए हैं। उनका कथन भी लिया गया है जो निष्पक्षता पूर्ण और पारदर्शी पूर्ण नहीं है।वहीं पीड़ित छात्राओं के अभिभावकों को भी नहीं बुलाया गया था। इससे यह चरितार्थ होता है कि जांच में लीपापोती करने का पूरा प्रयास किया गया है।

इस मामले में पंडों समाज के प्रांतीय अध्यक्ष उदय पंडों ने जानकारी देते हुए बताया कि अधीक्षिका के द्वारा छात्राओं को प्रताड़ित करने जांच टीम को गुमराह करने का कार्य किया गया है। उनके विरुद्ध निलंबन और पद से हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समाज प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

समाचार पचीसा
रायपुर, मंगलवार 16 जुलाई 2024

संक्षिप्त समाचार

उप मुख्यमंत्री साव ने एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का किया उद्घाटन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज

राजधानी रायपुर के शंकर नगर में एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। उन्होंने बैंक के अधिकारियों और खाताधारकों को बधाई देते हुए कहा कि एचडीएफसी बैंक ने कम समय में ही अपनी सेवाओं से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की है। किसी संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन में टीम-वर्क की अहम भूमिका होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एचडीएफसी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी अपनी बेहतर टीम-वर्क से रायपुरवासियों को अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विश्वास जताया कि एचडीएफसी बैंक से बैंकिंग सेवाओं की जरूरत वाली योजनाओं में राज्य सरकार और हितग्राहियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख श्री इकबाल सिंह ने उद्घाटन कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक के पिछले 30 वर्षों के सफर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शंकर नगर की यह नई शाखा छत्तीसगढ़ में बैंक की 204वीं और रायपुर शहर की 30वीं शाखा है। बैंक के सर्किल प्रमुख श्री दीपक अग्रवाल, श्री विकास गोयल, श्री सुबीर बनर्जी और शाखा प्रबंधक श्री रवीश शाह भी उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे।

मुख्यमंत्री से एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक चंद्रशेखर ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में एसबीआई के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक श्री चंद्रशेखर शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा से छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में बैंकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर इलाकों खासकर गावों तक बैंक शाखाओं का और अधिक विस्तार हो ताकि दूरस्थ क्षेत्र के अधिक से अधिक ग्रामीण-जन बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन सकें। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में वित्तीय समावेशन बढ़ाने और ग्रामीणों को बैंकिंग साक्षरता से जोडने् पर बल दिया। मुख्यमंत्री को श्री शर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस दिशा में उठाये जा रहे कदमों और आगे की कार्ययोजना के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर उपमहाप्रबंधक रायपुर श्री राकेश कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे।

प्रतिभावान बच्चे हुए सम्मानित

रायपुर। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा रविवार को सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में समाज के दसवीं व 12वीं परीक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश तिवारी ने बताया कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है तथा वे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए संस्था के प्रयासों को धन्यवाद दिया। सम्मानित होने वाले बच्चों में एक अथर्व दीवान जिसने आईसीएसई के दसवीं कक्षा में 95 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। वहीं माही तिवारी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 12वीं में 89 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे व गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने बच्चों को प्रेरणादायक प्रसंग सुनाते हुए उन्हें सम्मानित किया।

एक्स हैंडल पर मोदी के फॉलोवर्स 100 मिलियन पार

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक्स हैंडल पर फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन हो गयी है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलोवर्स वाले राजनेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की दुनिया भर में लोकप्रियता अद्वितीय है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोवर्स होने पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा 100 मिलियन पार, मोदी का परिवार वसुधैव कुटुम्बकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं।

मलेरिया से दो छात्राओं की मौत के बाद बीजापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री

बोले- सभी अस्पतालों में होगी सुधार, कांग्रेस काल में 3 गुना बढ़ा मलेरिया

रायपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे हैं। इस दौरान मंत्री जायसवाल जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही कन्या आवासीय पोटाकेबिन बीजापुर का निरीक्षण किया। इसके अलावा व्यवस्था का जायजा लिया।

भोपालपटनम ब्लाक तारलागुड़ा व संगमपल्ली कन्या आवासीय विद्यालय की दो छात्राओं की मलेरिया से मौत की खबर के बाद सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री हेलीपेड से सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, यहां उन्होंने भर्ती मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना।

स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजापुर की ही नहीं बल्कि प्रदेशभर के उन अस्पतालों की व्यवस्था दुरस्त की जाएगी, जहां की व्यवस्था दुरस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजापुर जिला अस्पताल में जो सुविधा नहीं है, वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आने वाले मौसमी बीमारियों से निपटने सरकार कटिबद्ध है।

प्रदेश के सभी अस्पतालों में इलाज के लिए सारी सुविधा सहित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। छात्राओं की मौत पर उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियों की मौत मलेरिया से या अन्य किसी बीमारी से हुई हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से जानकारी लेकर इस जो भी कार्यवाही हो कि जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ पूर्व मंत्री व बीजापुर के पूर्व विधायक महेश गागड़ा भी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में मच्छरों से बच्चों की मौत, 200 और बीमार

बीजापुर दौरे पर जाने से पहले श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में छत्तीसगढ़ में मलेरिया प्रति 1000 लोगों में 11 का आंकड़ा था, जो पिछले कांग्रेस शासनकाल में तीन गुना बढ़ गया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- हर साल की तरह इस साल भी मौसमी बीमारियां शुरू हो गई है। बस्तर के बीजापुर में मलेरिया से मौत की जानकारी मिली है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से जानकारी लेने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर दौरे पर जाने को कहा। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम, हेल्थ सेक्रेट्री, हेल्थ एमडी भी बीजापुर जा रहे है। बीजापुर जिला अस्पताल जाकर प्रभावित लोगों से मिलेंगे। पोटाकेबिन का मुआयना कर मलेरिया मुक्त करने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। बीजापुर जिला प्रशासन और बस्तर संभाग के हेल्थ अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी।

पोटकेबिन में मलेरिया से मौतों के मामले में कांग्रेस के हमले पर मंत्री जायसवाल ने कहा- विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पूरे सशक्त विपक्ष के तरह हर मुद्दे को उठाए। कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर जायसवाल ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में ज्यादा लोग मलेरिया से पीड़ित थे। उस समय मलेरिया से मौतें भी ज्यादा हुई थी। हमारी सरकार मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में पूरा काम कर रही है। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगाया जाएगा। मच्छरदानी बांटी जाएगी। लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। मलेरिया पीड़ित लोगों की दोबारा जांच की जाएगी।

जायसवाल ने आगे कहा- साल 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग मलेरिया प्रभावित थे। साल 2023 में जब दोबारा सत्ता संभाली तो प्रति 1000 लोगों में 35 लोग मलेरिया प्रभावित हुए। यानी कांग्रेस कार्यकाल में तीन गुना मलेरिया बढ़ा। भाजपा सरकार ने सरगुजा को मलेरियामुक्त किया। बस्तर के कुछ जिले मलेरिया प्रभावित थे जो बढ़कर अब 5 जिले हो गए हैं। पूरे बस्तर को 5 साल के अंदर मलेरिया मुक्त किया जाएगा।

प्रदेश में पैर पसार रहा डायरिया, 10 हजार से ज्यादा लोग पीड़ित

छत्तीसगढ़ में लगातार डायरिया अपना पैर पसार रहा। प्रदेशभर में डायरिया के 10 हजार 8 सौ 30 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीजापुर में सबसे ज्यादा 1306 मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में एक हजार 36 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं डायरिया से अब तक पांच मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डायरिया के प्रकोप से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और उचित इलाज के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है। जहां-जहां डायरिया के मरीज़ मिल रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया पर नियंत्रण पाया है। इलाज के लिए तमाम व्यवस्था कर दी गई है। बासी खाना और गंदे पानी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी तक एक भी व्यक्तियों की मौत सिर्फ डायरिया से नहीं हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है वो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे।

रायपुर नगर निगम में काबिल अफसरों की कमी?

रिटायरमेंट के बाद भी कार्यपालन अभियंता एसके पाण्डेय संविदा में बने जोन कमिश्नर

रायपुर। लगता है रायपुर नगर निगम में काबिल अफसरों की कमी हो गई है- ऐसा इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी नगर निगम के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने जोन 9 की कमान रिटायर्ड कार्यपालन अभियंता एसके पाण्डेय को सौंपकर रखी है। जबकि नगर निगम में इस पद के लिए कई अधिकारियों को नगर निगम हेड ऑफिस में जोन कमिश्नर के पद पर पदस्थ होने का इंतेजार कर रहे है।

सूत्रों के मुताबिक रिटायमेंट के बाद संतोष पाण्डेय को 1 साल की संविदा अवधि पर नगर निगम में नियुक्ति दी गई और निगम आयुक्त ने उन्हें जोन कमिश्नर के पद पर पदस्थ किया, क्योंकि यहां पदस्थ करने का विशेषाधिकार आयुक्त का होता है। अब जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी संविदा अवधि बढ़ाने के लिए पुन: आवेदन किया है, जिसे बढ़ाने की तैयारी है।

अधिकारियों और नेताओं के हाथ देखते है संतोष पाण्डेय

नगर निगम के एक सूत्र ने बताया कि संतोष पाण्डेय ज्योतिष भी है। वे अधिकारियों और नेताओं के हाथ देखकर उनका भविष्य बताते है, लेकिन इसकी फीस वो नहीं लेते है। संभवत: यही कारण है कि रिटायमेंट के बाद भी उन्हें संविदा पर पदस्थापना दी गई, ये जांच का विषय है कि उन्हें ये संविदा पर टैलेंट के आधार पर दिया गया है या इसके पीछे की वजह कुछ और है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त का पक्ष लेने उन्हें फोन किया गया, लल्लूराम की टीम उनके ऑफिस भी गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

शराब घोटाला मामला : मेरठ कोर्ट में पेश हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा

रायपुर। शराब घोटाला मामले के आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को यूपी पुलिस ने मेरठ कोर्ट में पेश किया। बता दें कि नकली होलोग्राम बनाने के मामले पर ट्रांजिट वारंट पर आरोपी अनिल टूटेजा को पुलिस यूपी लेकर पहुंची है। कोर्ट में पेशी के बाद वापस केंद्रीय जेल रायपुर में लाकर सुपुर्द करेगी।

बता दें कि यूपी पुलिस ने अनिल टुटेजा के प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। नकली होलोग्राम बनाने के मामले में अनिल टुटेजा के खिलाफ भी उत्तरप्रदेश में अपराध दर्ज है। इससे पहले मामले में यूपी पुलिस ने अनवर ढेबर और पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी की है।

जुलाई 2023 में नकली होलोग्राम मामले में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 मई को यूपी एसटीएफ ने प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गुप्ता ने अनवर और अरुणपति का नाम लिया था।

एफआईआर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्रालि को टेंडर दिया था। कंपनी के मालिकों की मिलीभगत से निविदा शर्तों को संशोधित किया गया और अवैध रूप से निविदा आवंटित की गई। बदले में कमीशन लिया गया और डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ सक्रिय गैंग को की गई।

कांग्रेस को भरोसा नहीं हो पा रहा कि वह सत्ता से बाहर हो गई है: अरूण साव

तुष्टिकरण के नाम पर कर रहे हैं छत्तीसगढ में वे राजनीति, कानून व्यवस्था भी बिगाड़ रहे

रायपुर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद हम छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वह सत्ता से बाहर हो गई है। उनमें छटपटाहट और तड़पड़ाहट नजर आ रही है। कांग्रेस का काम अराजकता पैदा करने का तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति करने, कानून व्यवस्था को बिगाडने् का है और वो अभी भी यही कर रही है।

बलौदाबाजार में इसकी बानगी भी देखने को मिली। भूपेश गुट के जिला अध्यक्षों को हटाए जाने की चर्चा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जुतम पैजार चल रहा है। समीक्षा बैठकों में एक दूसरे की पोल खोली गई। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व और नियत कुछ भी नहीं है। जनता में विश्वसनीयता भी ख़त्म हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर सर्वे कराए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सर्वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कराए होंगे। सबका सर्वे जनता ही तय करती है। जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। निकाय और पंचायत चुनाव में जनता इसी तरह का निर्णय करेगी।

पटवारी हड़ताल में मस्त, काम नहीं होने से आम आदमी पस्त

■ **पूरे प्रदेश के पटवारियों ने किया काम बंद**

रायपुर। राजस्व अमले का पटवारी एक अहम अंग है यदि काम बंद कर दिया तो पूरे विभाग का काम चौपट हो जाता है। पिछले सप्ताह भर की हड़ताल से लोगों का काम प्रभावित हो रहा है और वे यहां से वहां केवल चक्कर काट रहे हैं। हालांकि पटवारी हड़ताल के कारण शासन ने आनलाइन रेकार्ड के आधार पर तहसीलदारों को विभिन्न जरूरी काम करने का निर्देश दिया है। पटवारी हड़ताल के कारण राजस्व पटवारी संघ अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की बेमियादी हड़ताल से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इन दिनों स्कूल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से उक्त दस्तावेज बनाना जरूरी हो गया है। इसके बाद भी वर्तमान में लाखों प्रामण पत्र अभी पेडिंग लिस्ट में डाल दिए गए हैं। प्रदेश में आय के 113540, मूल निवासी के 60501,अनुसूचित जाति के 46851,ओबीसी जाति के 47375 प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। रायपुर जिले का आंकड़ा देखें तो 2208 आय, 2353 मूल निवासी, 600 एससीएसटी के जाति प्रमाण पत्र और 1688 ओबीसी के प्रमाण पत्र बनने को लंबित हैं।

उप मुख्यमंत्री ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को किया सस्पेंड

शिकायत मिलने के बाद की कार्रवाई

बालोद। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को बालोद जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कमियां पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारिओं को जमकर फटकार भी लगाई। मार्री बंगला देवरी के तहसीलदार नीलकंठ जन बन्धु के खिलाफ किसानों से शिकायत मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया, इसी तरह गुरुर थाना प्रभारी डी के कुर्रे को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर पाने की वजह से निलंबित कर दिया गया है।

समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने लॉ एंड आर्डर ठीक नहीं करने पर एक थानेदार को सस्पेंड किया है, इसके अलावा किसानो से मिली शिकायत के बाद एक तहसीलदार को भी सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां पर अनेक बातों के लिए आज सहमति हुई है। जिले में सभी लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने, लोगों के लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था करने और बालोद जिले के सभी मुख्यालयों में स्थित प्राइमरी स्कूलों में बायोमैट्रिक और सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है कि राजस्व कैंप लगाकर जल्द से जल्द किसानों की समस्या का निराकरण करें। अगले प्रवास तक कई तरह के कार्य पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

मानसून सत्र 22 जुलाई से, 900 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे

रायपुर। प्रदेश में मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरु होकर 31 जुलाई तक चलेगा। 10 दिवसीय मानसूत्र सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 900 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से कई संशोधन विधेयक सदन में पेश हो सकते हैं। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच भी सदन में गूंजेंगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 की महालेखाकर की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय ले सकती है, जिसमें मतांतरण संशोधन विधेयक, नक्सलवाद पुर्नवास नीति शामिल हैं। मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पंचायत, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह, जल संसाधन, कृषि, वन, स्वास्थ्य आदि विभागों को लेकर सवाल पूछे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सत्र के लिए सवालों की फेहरिस्त तैयार की है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को सुगमता से मिल रहा है खाद-बीज

23.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की हो चुकी है बोनी, किसानों को अब तक 8.61 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.85 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 8.61 लाख मीट्रिक टन खाद जो लक्ष्य का 63 प्रतिशत वितरित हो चुका है। इसी प्रकार किसानों को 7.85 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। राज्य में अब तक 23.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 08 जुलाई 2024 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 200.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1236 मिमी है।

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 9.04 लाख क्विटल बीज का भंडारण कर अब तक 7.85 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 13.68 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 12.80 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 8.61 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 63 प्रतिशत है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के किसानों को सुगमता से उनकी मांग के अनुरूप खाद-बीज सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा है।

विश्व स्तर पर भारत अपनी भूमिका निभाने को तैयार

कल्याणी शंकर

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक सांझेदारी को मजबूत करना था। रूस के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने इसे अशांत भू-राजनीतिक माहौल के बीच 'ऐतिहासिक और खेल बदलने वाला' बताया। मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन ने दो प्रभावशाली देशों रूस और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संबंधों के लिए मोदी के कुशल प्रबंधन को उजागर किया। रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध के बावजूद, दोनों नेताओं द्वारा अपनी बैठकों के दौरान दिखाई गई गर्मजोशी मोदी की रूस यात्रा के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। मोदी पिछले 10 वर्षों में 6 बार रूस का दौरा कर चुके हैं और कम से कम 17 बार पुतिन से मिले हैं। इस यात्रा के दौरान पुतिन के निजी आवास पर रात्रिभोज पर बातचीत साढ़े 4 घंटे तक चली, जबकि आमने-सामने की बातचीत अढ़ाई घंटे तक चली। इससे दोनों नेताओं को मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला। वर्तमान यात्रा ने भारत और रूस के बीच स्थायी संबंधों और पुतिन के साथ आमने-सामने की चर्चा को उजागर किया। इसमें चीन और घरेलू राजनीतिक स्थिति भी शामिल है। शिखर सम्मेलन ने यू.एस.-भारत संबंधों के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। यह ऐसे असुविधाजनक समय पर हुआ जब यूक्रेन में संघर्ष जारी था। बैठक का प्रभाव यह था कि भारत रूस और यू.एस. के साथ संबंधों को संभाल सकता है। मोदी का पुतिन के साथ 'गले मिलना' और पुतिन द्वारा मोदी को अपना 'सबसे अच्छा दोस्त' कहना शायद यू.एस. और पश्चिम में भौंहें चढ़ा सकता है। सी.एन.एन. ने कहा, ''व्लादिमीर पुतिन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आवास पर मिनी इलैक्ट्रिक कार में घुमाने का दृश्य दिखाता है कि दोनों नेता कितने घनिष्ठ हो गए हैं।'' इस यात्रा ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। इसने विज्ञान, व्यापार और जलवायु परिवर्तन पहलों सहित नए समझौतों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत और रूस का लक्ष्य पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन तक बढ़ाना है। प्रस्तावित नए परमाणु रिएक्टरों सहित भारत का ऊर्जा भविष्य आशाजनक था। जिस तरह से नई दिल्ली रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकती है, वह आशावाद की भावना प्रदान करता है। बाइडेन प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत की महत्वपूर्ण सांझेदारी की पुष्टि आश्वस्त करने वाली है। यह अमरीका-भारत के बढ़ते संबंधों की मजबूती और स्थिरता को रेखांकित करता है। कई अमरीकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उदाहरण के लिए, पेंटागन के प्रैस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि अमरीका भारत को एक रणनीतिक सांझेदार के रूप में देखता है और मजबूत संवाद में शामिल रहेगा। इस संवाद में रूस के साथ भारत के संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा शामिल है। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका यूक्रेन में स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत को प्रोत्साहित करना जारी रखता है। उन्होंने यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने में भारत के समर्थन के महत्व पर जोर दिया। भारत ने हाल के वर्षों में रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। रूस भारत के हथियारों का प्राथमिक स्रोत होने के बावजूद, नई दिल्ली ने संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और इसराईल से भी अधिक हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। भारत अपनी तोपों की खरीद के लिए अपने विकल्पों का विस्तार कर रहा है। मोदी की यात्रा के दौरान, किसी नए हथियार सौदे की घोषणा नहीं की गई। हालांकि, विशेषज्ञ भारत में अमरीकी राजदूत एरिक गार्सेटी के हालिया भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि भारत-अमरीका संबंध मजबूत हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

अब मोदी के अहम चुनौतियां

शेखर गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है। उनका यह कार्यकाल पिछले दो कार्यकाल से काफी अलग है और यह बात वह किसी और से बेहतर जानते हैं। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव ऐसा नहीं रहा है कि वे मिलीजुली सरकार चला सकें। वास्तविक मुद्दा बहुमत का न होना नहीं है। उनके पास 240 सीट हैं जो काफी हैं, कोई साझेदार भी ऐसा नहीं है जो उनकी सरकार को गिरा सके। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस कार्यकाल की शुरुआत भी पिछले दो की तरह ही की। उनके लिए यह दिखाना महत्त्वपूर्ण है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में अंतर आंकड़ों का नहीं बल्कि उस नए माहौल का है जिसका अनुमान मैंने चुनाव नतीजों के दिन लगाया था। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम विभिन्न खेलों के रूपकों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। पहले वे खेल जिनमें सीधी टक्कर और शारीरिक संपर्क होता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके साझेदारों को बॉक्सिंग मैच में अंकों के आधार पर मिली जीत के समान विजय हासिल हुई। जीत का अंतर बहुत कम नहीं था लेकिन यह पिछले दो चुनावों की तरह नॉकआउट और एकतरफा भी नहीं थी। उसके प्रतिद्वंद्वी भी कुछ पंच लगाने में कामयाब रहे और वे अभी भी रिंग में लड़ने के लिए मौजूद हैं। वे यह भी मानते हैं कि वर्तमान विजेता को हराया जा सकता है। यही बदलाव है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और 'इंडिया गठबंधन के अन्य नेता किस प्रकार राजनीतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। वर्ष 2014 और 2019 के चुनावों के बाद वे अपने जख्म सहलाने लगे थे या किसी आध्यात्मिक चिंतन में लिप्त हो गए थे। अब हम कहीं अधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। वर्ष 2024 के चुनाव नतीजों की तुलना एक ऐसे क्वालिफायर से कीजिए जिसकी बदौलत विपक्ष को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विजेता को चुनौती देने का मौका मिला हो। टेस्ट क्रिकेट में एक-एक सत्र के हिसाब से खेला जाता है। इस टेस्ट में पहला सत्र होगा इस वर्ष के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव। इनमें से हर जगह प्रतिद्वंद्वी मजबूत हैं। हम जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वहां अलग तरह की चुनौतियां हैं।

इस सत्र के समाप्त होते ही अगले सत्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। अगले वर्ष की शुरुआत दिल्ली से होगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल की सजा ने इस संघर्ष को अलग धार दी है। उसके बाद सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ दिन का अंतिम सत्र होगा। इन तीन सत्रों में कम से कम दो जीतने वाले को 2029 के चुनाव की दिशा में बढ़त हासिल होगी। मोदी ने इस कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ प्रवेश किया है जो चुनाव अभियान के दौरान ही उभरने लगी थीं। कानून बनाने को लेकर अब तक के रवैये में कई बदलाव लाने होंगे। अहम कानूनों को एक झटके में पारित करने का समय अब नहीं रहा। जरूरी संविधान संशोधनों के लिए भी प्रतीक्षा करनी होगी। 'अबकी बार 400 पार' के नारे ने संविधान को लेकर व्यापक असुरक्षा को जन्म दिया। सरकार को कुछ समय तक किसी संशोधन का प्रस्ताव रखने से भी गुरेज करना होगा। निश्चित तौर पर एक हल यह होगा कि विपक्ष से बातचीत करके इन संशोधनों को पेश किया जाए। इसके लिए मोदी युग में भाजपा की राजनीति में आमूलचूल बदलाव लाना होगा।

पहले संसदीय सत्र में तो किसी तरह की राहत मिलती नहीं नजर आई। इससे तो यही अंदाजा लगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझे हुए हैं और उनके बीच पूरी तरह अविश्वास का माहौल है। नई सरकार के सामने जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है 'जय जवान/जय किसान' का जाल। दो दशकों में मोदी ने अपनी छवि किसानों और सशस्त्र बलों के हिमायती के रूप में गढ़ी है। इन चुनावों में इस छवि को झटका लगा क्योंकि पार्टी को कृषि और सैनिकों की अधिकता वाले राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में झटका लगा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का शुरुआती वादा बुरी तरह विफल रहा और कृषि सुधारों को लेकर होने वाली बहस को उन कानूनों ने बरबाद कर दिया जिन्हें अध्यादेशों के माध्यम से लाया गया और फिर संसद द्वारा पारित किया गया। अब क्या मोदी उन पर पुनर्विचार कर सकते हैं और विपक्ष को साथ ला सकते हैं? अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका बुनियादी विचार क्या होगा?

इस बात की संभावना भी कम है कि नए सिरे से उत्साहित विपक्ष रचनात्मक प्रतिक्रिया देगा। खासकर तब जबकि एक अंतराल के बाद मैच का एक और सत्र होने वाला हो। दूसरी ओर अगर अब सरकार कृषि को लेकर और लोकप्रिय कदम उठाती है तो यह निराश करने वाली बात होगी। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा और उसकी दरें बढ़ाना और कृषि माफी करना तथा साथ ही जैव प्रौद्योगिकी एवं जीएम बीजों पर स्वदेशी के तहत रोक लगाना।

भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शोध शाखा की ओर से आई साहसिक रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में राह दिखाती है। स्टेट बैंक इस बात को रेखांकित करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कैसे चंद किसानों के लिए काम करती है और कुल कृषि उत्पादन का छह फीसदी ही इसमें आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में अधिक साहसिक सुधारों की आवश्यकता है जिसके तहत बाजार और एमएसपी से दूरी बनानी होगी। क्या भाजपा की राजनीति में ऐसे मसलों पर कदम उठाने की कोई गुंजाइश बची है। शिवराज सिंह चौहान के रूप में पार्टी ने कृषि मंत्री के रूप में बढ़िया चयन किया है। बीते करीब दो दशक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खेती में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्हें एक मिलनसार, समझौते करने वाला और राजनीतिक रूप से कुशल राजनेता माना जाता है। वह भाजपा के वाजपेयी युग के गिनेचुने नेताओं में शामिल हैं। हालांकि कठिन होगा लेकिन अगर इन विषयों पर उन्हें समर्थन मिल पाता है तो यह सुखद होगा।

अगर किसान मुद्दे पर लगा झटका विफल कृषि सुधारों से उत्पन्न हुआ है तो जवानों के मुद्दे पर नकारात्मकता भी ऐसे ही दंभ की वजह से उत्पन्न हुई। सेना में छोटी अवधि वाले कार्यकाल खासकर अन्य रैंक के लिए ऐसे कार्यकाल का विचार तीन दशक पहले आया था। इससे पेंशन का बढ़ता बोझ कम होता है और आधुनिकीकरण के लिए अधिक गुंजाइश बनती है। परंतु इसका बड़ा लाभ यह भी है कि सेना के जवान युवा रहते हैं। फिलहाल उनकी औसत आयु 33 वर्ष जो बहुत अधिक है। यह बदलती तकनीक के लिहाज से भी उपयुक्त होता है। यह युवा भारतीयों को अवसर देता है कि वे सशस्त्र बलों में सेवाएं दें और अधिक कुशल तथा रोजगार क्षमता के साथ सेना से निकलें।

कृषि कानूनों की तरह यह भी चर्चा के बिना लागू की गई योजना थी। अब अग्निपथ में कई बदलाव किए जाएंगे। उदाहरण के लिए आप एक ही यूनिट के और एक ही बंकर के और एक ही बम से हताहत होने वाले दो सैनिकों के लिए अलग-अलग हर्जाने की व्यवस्था को कैसे उचित ठहराएंगे? क्या दोनों को अलग बिल्ला पहनाना और दो वर्ग तैयार करना जरूरी है? आपात काल और अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में मॉडल पहले से तैयार थे जिनके तहत सेवा में रहने के दौरान सभी समान थे लेकिन सेवा अवधि की लंबाई के मुताबिक उनके कार्यकाल तथा क्षतिपूर्ति अलग-अलग थे। ऐसा बड़ा बदलाव हमेशा चुनौती लाता है लेकिन अधिक धैर्य तथा अंशधारकों से बातचीत से मुश्किलें कम होतीं। मोदी सरकार को इन चुनौतियों का सामना उस ताकत के बिना करना होगा जिसकी उसे आदत थी। इस दौरान उसे एक के बाद एक लगातार हमले भी झेलने होंगे। हम जानते हैं कि समय के साथ अक्सर पिच भी खराब होती जाती है। यही वजह है कि तीसरा कार्यकाल पहले दो कार्यकाल की तरह नहीं होगा।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

उप-पुराण (भाग-3)

गतांक से आगे...

पुराणों की संख्या अठारह है, यह पूर्वोक्त नामों की गणना से भली भांति ज्ञात हो सकता है, परन्तु येन केन प्रकारेण पुराणों के खण्डन की शपथ खाने वाले लोगों ने कई प्रकार के हेत्वाभास देकर पुराणों की संख्या को न्यून या अधिक बनाने का शिरतोड़ प्रयत्न किया है।

यद्यपि किसी ग्रन्थ की हेयोपादेयता में संख्या का वैशिष्ट्य कुछ मूल्य नहीं रखता तथापि ऐसे स्वयम्भू समालोचक कितनी योग्यता के अधिपति होते हैं- यह प्रकट करने के लिए इस विषय पर भी विचार करना अनुचित न होगा ।

शङ्कावादियों का कथन है कि अग्नि, कूर्म और देवीभागवतादि कई पुराणों में शिव-पुराण की गणना नहीं है किन्तु इसके स्थान में वायु पुराण का नाम लिखा है जबकि अन्यान्य पुराणों में शिव पुराण को गिना है। इस प्रकार दोनों को पुराण मान लेने पर पुराणों की संख्या 16 हो जाती है। इस नाम भेद पर भी शङ्कावादियों को खासी बकझक का अवसर मिल जाता है। परन्तु उन्हें यह विदित नहीं कि एक ग्रन्थ के एकाधिक नाम भी हो सकते हैं। वैदिक सहित्य में चौथे वेद का नाम अथर्ववेद प्रसिद्ध है परन्तु कई स्थलों पर इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी स्मरण किया गया है। यथा:- चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो ब्रह्मवेद:।

अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित होने के कारण इसे अथर्व कहते हैं और होता, अध्वयू, उद्गाता तथा ब्रह्मा नामक ऋत्विजों में ब्रह्माधिकृत होनेके कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं।

संस्कृत साहित्य में भी उत्तर-मीमांसा या वेदांत दर्शन और शिशुपालबध या माघ काव्य आदि एक 2 ग्रन्थ के दो दो नाम पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक ही पुराण के शिथ वायु दो नाम हैं।

क्रमश: ...

साझा सेवा केंद्र (सीएससी) दिवस

श्रीराम शर्मा

कॉमन सर्विस सेंटर या सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण इलाकों में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। सीएससी- कॉमन सर्विस सेंटर या कहें जन सेवा केंद्र, ऐसी जगह होती है जहां सरकार से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी जाती है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं और इंटरनेट से जुड़े काम किए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये सेंटर 'एक दुकान-कई सारे काम' की तर्ज पर चलते हैं। यहां आप जीएसटी से जुड़े काम करवा सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाने-पीने की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुटिर उद्योग-धंधे के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकारी स्कीमों का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। खेत की खसरा-खतौनी निकवा सकते हैं। किसान सम्मान निधि की स्थिति जांच सकते हैं। कुल मिलाकर ऑनलाइन होने वाले अनेक काम इन जनसेवा केंद्र के माध्यम से करवाए जा सकते हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर तमाम काम करने की जगह के साथ-साथ ग्रामीण नौजवानों के कमाई का भी एक बड़ा संसाधन है। कोई भी पढ़ा-लिखा युवक जनसेवा केंद्र खोलकर खुद का रोजगार खड़ा कर सकता है और घर बैठे ही अच्छी-खासी कमाई कर सकता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने सामान्य सेवा केंद्र योजना शुरू की है। इसका मकसद ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के साथ-साथ ग्रामीण लोगों को अपने छोटे-मोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना भी है। जिन लोगों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे इन कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना काम आसानी से और बहुत कम खर्चे पर करवा सकते हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर या जनसेवा केंद्र एक तरह का साइबर कैफे है। यहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं। कोई व्यक्ति जनसेवा केंद्र से मंडीभाव या बाजार की जानकारी हासिल कर सकता है। रेल, बस या हवाई टिकट बुक कराए जा सकते हैं। मोबाइल फोन रिचार्ज कराया जा सकता है। बिजली के बिल या अन्य बिल जमा किए जा सकते हैं। स्कूल-कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म भरे जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र बनवाया जा सकता है। पेंशन से जुड़ी सेवाएं ली जा सकती हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा आपके पास टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। टीईसी कम्प्यूटर का बेसिक कोर्स होता है। मामूली फीस चुकाने के बाद इस कोर्स को किया जा सकता है। टीईसी के बारे में ज्यादा जानकारी www.cscentrepreneur.in से हासिल की जा सकती है। इन सबके बाद आपको भारत सरकार की वेबसाइट www.csc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है।

नेपाल : बेमेल गठबंधन के सामने होंगी चुनौतियां

केएस तोमर

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो साधनों, नैतिकता और मूल्यों का पूरी तरह से अनादर कर अंत तक अड़े रहने के मैकियावैली सिद्धांत के अनुपालन की राजनेताओं की प्रवृत्ति नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के मामले में सटीकता से दिखती है, जो नेपाली संसद में विश्वासमत हासिल करने के दौरान अपमानजनक ढंग से हारकर अपना पद गंवा बैठे हैं। प्रचंड को मात्र 63 वोट ही मिले, जबकि उनके खिलाफ नेपाली कांग्रेस और नेपाल (यूएमएल) के नए गठबंधन को कुल 194 वोट मिले। नए गठबंधन को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एवं जनता समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दलों का भी समर्थन मिला। 275 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए मात्र 138 सीटें चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है।

इस बीच अच्छी बात यह है कि सीपीएन-यूएमएल के विदेश मामलों के प्रमुख और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉ. राजन भट्टाराई ने जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि नेपाल की प्रगति या नेपाली नागरिकों का कल्याण केवल भारत समर्थक रुख अपनाकर ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओली नेपाल-भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इच्छुक हैं, ताकि आधुनिक युग की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

नेपाल में लोकतंत्र की नाजुक स्थिति के कारण निरंतर अस्थिरता सरकार की पहचान रही है, जो तेरह वर्षों के लोकतंत्र में 16 बार सत्ता परिवर्तन से स्पष्ट है, जिससे देश के आम लोगों के हितों पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ही है, देश आर्थिक संकट और ऋण देनदारियों, विशेष रूप से चीनी कर्ज के जाल में फंस गया है। नई सरकार का डेढ़ साल तक नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री और कट्टर कम्युनिस्ट नेता ओली करेंगे, जिसके बाद समझौते के अनुसार, शेष कार्यकाल के लिए देउबा प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे।

ओली एवं देउबा की नई गठबंधन सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यही चुनौतियां उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगी, अन्यथा इसका नतीजा मध्यावधि चुनाव के रूप में सामने आ सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कम्युनिस्टों (चीन समर्थक) और नेपाली कांग्रेस (भारत समर्थक) की विरोधी विचारधाराओं वाली नई सरकार को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

दूसरी बात, ओली और देउबा गठबंधन के समक्ष दो क्षेत्रीय शक्तियों यानी भारत और चीन से समान दूरी बनाए रखने की बाध्यता होगी, जिनके नेपाल के मामलों में भू-राजनीतिक और सामरिक हित जुड़े हैं। तीसरी बात, इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए ओली ने भारत विरोधी कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने एक नया नक्शा बनवाया था, जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी सहित भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इससे भारत नाराज हो गया और नक्शे को खारिज करते हुए उसे संबंधों को खराब करने का प्रयास बताया था। अब, गठबंधन में प्रमुख भागीदार के रूप में देउबा की जिम्मेदारी होगी कि वह ओली को भारत विरोधी मानसिकता से निकलने के लिए मनाएं और दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों की रक्षा करें।

चौथी बात, प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने हमेशा चीन के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत दिए हैं। चीन नई सरकार से भी बेल्ट ऐंड रोड (बीआरआई) पहल पर आगे बढ़ने की उम्मीद करेगा, क्योंकि प्रचंड ने 12 मई, 2017 को दोनों देशों के बीच हुए हस्ताक्षरित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ओली सरकार को भारत की तरफ से किसी भी अड़चन से बचने के लिए इसे स्थगित रखने के लिए तार्किक कदम उठाना होगा। प्रचंड ने सितंबर, 2023 में बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान बीआरआई को गति देने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता दोहराई थी।

अब ओली के लिए बीआरआई के संकल्प पर टिके रहना मुश्किल होगा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस पूरी तरह से इसके खिलाफ है, इसलिए इस मामले में प्रगति की संभावना दूर की कौड़ी लगती है। पांचवीं बात, भारत की अग्निपथ योजना से निपटना नई सरकार के लिए चुनौती होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत ने 15 जून, 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसे नेपाल में भी लागू किया गया था, लेकिन कुछ आपत्तियों की वजह से अब भी नेपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। जबकि फील्ड रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में ऐसे बेरोजगार युवा हैं, जो अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन पिछली दो सरकारों ने इसमें देरी की और तीसरी सरकार भी शायद उससे अलग नहीं होगी।

छठी बात, भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। नई सरकार एक नई रणनीति अपना सकती है, जिसमें भारतीय समकक्षों के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करने और सीमा विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाना शामिल है। तकनीकी और कूटनीतिक माध्यमों से सीमा विवाद के समाधान में तेजी लाने के लिए नेपाल-भारत संयुक्त सीमा आयोग को मजबूत करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अवैध गतिविधियों और अनधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए विवादित सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना, दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। सातवीं बात, चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि की तरह नेपाल को भी अपनी %ऋण नीति% में फंसा कर नेपाल को भारी कर्ज दिया है, जिसे चुकाने में सदियां लग सकती हैं।

अंत में, विवादित क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने और उपस्थिति का दावा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इन रणनीतियों को अपनाकर नेपाल की नई सरकार अग्निपथ योजना से उत्पन्न चुनौतियों और भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों का संतुलित और प्रभावी तरीके से समाधान कर सकती है। लेकिन नए गठबंधन का अस्तित्व पूरी तरह से साझेदारों के आपसी विश्वास और संतुलित कूटनीतिक रणनीति के कार्यान्वयन तथा दो क्षेत्रीय दिग्गजों को नाराज करने से बचने पर निर्भर करेगा, जिसका अतीत में अभाव रहा है।

आज का इतिहास

1894 आओकी-किम्बरली की संधि; जापान और इंग्लैंड ने संधि पर हस्ताक्षर किए।

1931 इथियोपिया के सम्राट हैली सेलासी ने राष्ट्र के फर्स्टकंस्ट्रेशन पर हस्ताक्षर किए, इतिहास में पहली बार एक निरपेक्ष रूप से अपने विषयों के साथ संप्रभुता साझा करने की मांग की।

1942 फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने 13,152 यहूदियों को गिरफ्तार किया।

1942 संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिनलैंड के साथ राजनयिक संबंध खतम किया।

1945 अमरीका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया।

1945 मैनहट्टन प्रोजेक्ट-ट्रिनिटी, पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट, न्यू मैक्सिको के आलमोगोर्डो के पास किया गया था।

1950 फुटबॉल विश्व कप के चौथे संस्करण के फाइनल में ब्राजील को हरा उरुगवे चैंपियन बना।

1950 कोरियन वॉर-ए कोरियन पीपुल्स आर्मी यूनिट ने इक्कीस अमेरिकी सेना के युद्ध बंदियों का नरसंहार किया।

1951 एशिया का देश नेपाल, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ।

1951 द कैचर इन द राई, जो एक अमेरिकी आने वाला उपन्यास है, जो जे.डी. सालिंगर द्वारा प्रकाशित किया गया था।

1965 दक्षिण वियतनामी कर्नल फाम नोक थोओ - एक अनिर्धारित कॉम्युनिस्ट जासूस - नौगीन खान के खिलाफ फरवरी 1965 में तख्तापलट के प्रयास के लिए अनुपस्थित में सजा सुनाए जाने के बाद नीचे शिकार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।

1981 महाथिर मोहमद को मलेशिया के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, एक पद जो उन्होंने 22 वर्षों तक रखा, जिससे वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति बन गए।

1988 पडी एशडाउन ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेट के नेता बने।

1990 फिलीपींस में 7.7 की तीव्रता के भूकंप में 400 लोग मारे गये।

1990 एक 7.8 एमएस भूकंप ने लूजॉन के घनी आबादी वाले फिलीपीन द्वीप पर हमला किया, जिसमें अनुमानित 1, 621 लोग मारे गए।

1993 ब्रिटेन की खुफिया सेवा, एमआई5 के किसी सदस्य ने फोटो खिंचवा कर पहली बार औपचारिक रूप से जनता के सामने अपनी पहचान खोली।

2004 शिकागो का मिलेनियम पार्क , वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा छत उद्यान, खोला गया।

क्या हरियाणा में तीसरे मोर्चे को एक-बार पुनः पंख लगेंगे?

कमलेश पांडे

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने और सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय मित्र दलों पर निर्भर रहने से इलाकाई पार्टियों के हौसले बुलंद हैं।इनका कहना है कि एक दशक बाद ही सही, पर गठबंधन राजनीति का दौर एक बार फिर से लौट आया है। अलबत्ता, भाजपा के कमजोर होने और कांग्रेस की मजबूती के बाद इन दोनों दलों के खिलाफ काम करते रहने वाले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। क्योंकि चुनावों में जब भी त्रिकोणात्मक संघर्ष की नौबत आती है तो प्रायः सत्तापक्ष लाभान्वित होता है। इस वर्ष के अंत में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है।

देखा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वहां पर कभी सत्तारूढ़ रही इंडियन लोकदल और कभी यूपी में सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। साथ ही, दोनों दलों के गठबंधन ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है, जो एनडीए के साथ रही जननायक जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के साथ रही आप आदि दलों को इस तीसरे गठबंधन के साथ लाने की कोशिश करेगी।

इस गठबंधन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलेगी और अन्य सभी दलों को साथ लेकर चलेगी। समझौते के मुताबिक, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इनैलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, जब जजपा और आप इनके साथ होंगे तो इनैलो और बसपा अपनी सीटों में से उन्हें भी सम्मानजनक सीटें देंगी, ताकि तीसरा मोर्चा मजबूत हो।

इसलिए सियासी हल्के में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भारत के उपप्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित इंडियन लोकदल ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र और पार्टी के इकलौते विधायक अभय चौटाला के नेतृत्व में दलितों की पार्टी बसपा से जो हाथ मिलाने की पहल की है, उसका दूरगामी असर हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों पर पड़ेगा। क्योंकि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनन्द ने यह घोषणा की है कि उनका गठबंधन अब बहुत दूर तक चलेगा।

चर्चा है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह पता चल गया कि स्थानीय जाट और एससी वर्ग ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है, जिससे वह राज्य में

मजबूती से पैर जमा चुकी है, तो उसे कमजोर करने के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर जाट परिवार के नेतृत्व वाली आईएनएलडी और दलित नेता मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी 10 साल बाद राज्य में सियासी लड़ाई के लिए एक साथ आई हैं।

जिस तरह से अचानक इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करने के लिए फिर से एक साथ आए हैं, उसके सियासी मायने साफ हैं। वह यह कि कांग्रेस को यहां मजबूत होने से रोका जाये, अन्यथा उनकी राजनीति पुनः खतरे में पड़ जाएगी। बताते चलें कि अप्रैल 2018 में आईएनएलडी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के नेतृत्व वाली बसपा पार्टी के साथ गठबंधन किया था और सकारात्मक परिणाम भी हासिल किया था। लेकिन 2018 में आईएनएलडी में विभाजन के बाद और 2019 के जींद उपचुनावों में आईएनएलडी के खराब प्रदर्शन के बाद ही बीएसपी ने गठबंधन खत्म करने का फैसला किया था। जो दोनों दलों के लिए आत्मघाती साबित हुआ। क्योंकि इससे पहले जब दोनों पार्टियों ने 1998 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन किया था, तो हरियाणा में इनेलो ने 7 और बीएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ने क्रमशः 4 और 1 सीट जीती भी थी। जबकि वर्तमान में आलम यह है कि 90-सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला हैं, जबकि बीएसपी का कोई सदस्य नहीं है।

यही वजह है कि गत गुरुवार को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनेलो महासचिव अभय चौटाला और मायावती के भतीजे व बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने घोषणा की कि हरियाणा स्थित पार्टी इनैलो 90 विधानसभा सीटों में से 53 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 37 सीटें बीएसपी को दी गई हैं। वहीं, इस गठबंधन के हिस्से के रूप में नेताओं ने इनेलो नेता अभय चौटाला को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का फैसला किया है, जो एक मजबूत सियासी कदम है।

इस दौरान सीएम इन वेटिंग अभय चौटाला ने कहा कि हमने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। क्योंकि आज आम लोगों ने भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस को दूर रखने का मन बना लिया है, जिसने दस साल तक राज्य को लूटा है। वहीं, बसपा नेता आकाश आनंद ने घोषणा की कि उनका गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे भविष्य में भी राज्य में अन्य चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इससे साफ है कि बसपा जाट लैंड समझे जाने वाले पश्चिमी उत्तरप्रदेश से लेकर राजस्थान तक इस गठबंधन को भुनायेगी और खुद को और अधिक मजबूत बनाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस गठबंधन की घोषणा के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया कि बसपा और इनेलो मिलकर जनविरोधी पार्टियों को हराने और नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। इससे यह साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का परोक्ष समर्थन करके बसपा को शून्य पर आउट करवाने वाली मायावती लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी हैं और यह उनका सबसे तगड़ा धमाका है। इससे अन्य राज्यों में भी बसपा को गठबंधन साथी मिलने के मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं।

बकौल मायावती, बहुजन समाज पार्टी व इण्डियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आमचुनाव में वहाँ की जनविरोधी पार्टियों को हराकर अपने नये गठबन्धन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चण्डीगढ़ में संयुक्त प्रेसवार्ता में की गयी। वहीं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां तक उम्मीद जताई कि दोनों दलों के बीच एकता से विरोधियों को हराने और नई सरकार बनाने में बहुत मदद मिलेगी।

उनकी इस घोषणा के बाद दिल्ली से हरियाणा तक यही चर्चा है कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करने वाली मायावती अब क्या हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगी? क्योंकि बीते आम चुनावों में हरियाणा में भाजपा की सीटें 10 से घटकर 5 रह गई, जबकि कांग्रेस ने 5 सीट झटक ली। कहने का तातपर्य यह कि वहां कांग्रेस ने बराबर-बराबर सीटें बांटीं। वहीं, खास बात यह कि सूबे में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित दो संसदीय सीटें अंबाला और सिरसा भी कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इस प्रकार आम चुनाव 2024 के नतीजों से साफ पता चलता है कि जाटों और अनुसूचित जातियों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है।

अमेरिकी राजनीति में बूढ़ों की भरमार क्यों है?

नीरज कुमार दुबे

इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन का मुकाबला उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप से होगा। लेकिन जिस तरह बाइडन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं उससे उनका चुनाव लड़ना संदिग्ध लग रहा है। हालांकि बाइडन अड़े हैं कि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर ट्रंप को हरा कर दिखाएंगे लेकिन अब उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस पक्ष में दिख रही है कि बाइडन राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जायें। हाल में आयोजित बहस के दौरान ट्रंप से मुकाबला करते हुए बाइडन पिछड़ गये थे उसको देखते हुए अमेरिका में यह भावना आ रही है कि किसी और को आगे किया जाये। देखना होगा कि बाइडन की पार्टी का अंतिम निर्णय क्या होता है। लेकिन दुनिया भर में इस समय जो बहस चल रही है वह यह है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में क्या कोई युवा राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है? हम आपको बता दें कि बात सिर्फ बाइडन की ही नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी उम्रदराज हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्यों किसी युवा को आगे नहीं किया जाता? वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ही बूढ़े हैं। अगर आप अमेरिकी संसद यानि कांग्रेस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उसके लगभग 20त्न सदस्य 70 या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि लगभग 6त्न सदस्य 40 से कम उम्र के हैं। कई हाई-प्रोफाइल अमेरिकी राजनेताओं की उम्र 80 के करीब या उससे अधिक है, जिसमें दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी शामिल हैं। सवाल उठता है कि अमेरिकी राजनीति में उम्रदराज लोगों का ही बोलबाला क्यों है? सवाल यह भी उठता है कि अमेरिकी कांग्रेस में युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? देखा जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली युवाओं के लिए बनाई ही नहीं गयी है। अगर कोई युवा अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह भारी भरकम खर्च का जुगाड़ कैसे करेगा? जबकि उम्रदराज और पहले से राजनीति कर रहे नेताओं के पास अपना अच्छा नेटवर्क होता है जिसके चलते वह अपने लिए चुनाव अभियान आसानी से चला सकते हैं और चुनाव में खर्च के लिए अच्छा खासा फंड भी एकत्रित कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राजनीति में शानदार चुनाव अभियान बहुत मायने रखते हैं। दूसरी ओर युवाओं के लिए राजनीति में आने का मतलब है कामकाज से कम से कम एक साल की छुट्टी। यदि कोई पहले से ही अमीर है, तो चुनाव लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, यदि उसके पास अच्छी खासी बचत है तब भी वह अपना काम चलाते हुए अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ा लेता है लेकिन अगर किसी के पास धन नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता। इसीलिए युवा अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंचने की दौड़ में शामिल नहीं हो पाते। इसके अलावा, संभावित युवा उम्मीदवारों को पैसे के अलावा समय की भी कमी का सामना करना पड़ता है। युवाओं के लिए स्थिर कॅरियर, परिवार शुरू करना और आर्थिक सुरक्षा प्राथमिकता होते हैं। जबकि उम्रदराज लोगों के पास समय भी होता है और आर्थिक सुरक्षा भी होती है तथा अनुभव भी होता है इसलिए वह युवाओं पर भारी पड़ते हैं। साथ ही कांग्रेस तक पहुंचने में रुचि रखने वाले बुजुर्ग अमेरिकियों को कुछ प्रमुख चुनावी लाभ भी मिलते हैं। जैसे अमेरिकी जनता का अक्सर यह मानना रहा है कि पुरानी पीढ़ी के लोग युवाओं की अपेक्षा ज्यादा गुणवत्ता वाला काम करते हैं। अमेरिकी मतदाता यह भी मानते हैं कि चूंकि उनका देश ही एक तरह से विश्व भर के मामलों में निर्णायक भूमिका निभाता है इसलिए सर्वोच्च पद पर किसी अनुभवी व्यक्ति का बैठना जरूरी है। साथ ही, अमेरिकी राजनीति में एक चीज और देखने को मिलती है कि कांग्रेस के लगभग सभी सदस्य जो पुनः चुनाव लड़ते हैं, वह अंततः जीत जाते हैं।

वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जन्मदिवस अर्थात् संकल्प दिवस

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों माताओं बहनों ने इस पवित्र पुण्य यज्ञ में अपनी आपनी आहुतियां दी है। ऐसा ही एक तेजस्वी व्यक्तित्व मनः पटल पर उभरता हैं, मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व का अनूठा संगम भारत की सबसे बड़ी महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की आद्य प्रमुख संचालिका वंदनीय मौसी जी लक्ष्मी बाई केलकर का। जिन्होंने न केवल स्वाधीनता संग्राम में ही बल्कि उसके बाद भी महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता,आत्म रक्षा, आत्म विश्वास के साथ स्वराष्ट्र तथा स्वधर्म के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी।

आषाढ़ शुक्ल दशमी 1827 शके, 5 जुलाई 1905 को श्री कमल भास्कर दाते जी के घर जन्मी नन्ही कमल, एक सुसंकृत परिवार में धर्म तथा कर्म की भरपूर शिक्षा प्राप्त की। कम उम्र में ही उनका विवाह विधुर पुरुषोत्तम राव से हो गया। अब वे लक्ष्मी बाई केलकर के नाम से जानी जाने लगी। पुरुषोत्तम राव की पहली पत्नी से 2 बेटियां थीं जिनका पालन पोषण,पति सेवा करते हुए वे मात्र 31 वर्ष की आयु में पति के निधन हो जाने पर विधवा होने का दंश झेला।

कौन जानता था कि ऐसी चुनौती भरे जीवन को नकारते हुए एक ऐसा आलौकिक व्यक्तित्व अस्तित्व में आएगा जो राष्ट्र सेविका समिति की आद्य प्रमुख संचालिका वंदनीय मौसी के रूप में एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र के लिए स्वयं प्रेरणा से प्रेरित बहनों का,सेविकाओं का न केवल भारत में अपितु समग्र विश्व में स्त्रियों में जीवन की नई प्रेरणा,उमंग, आशा, विश्वास,धर्म तथा राष्ट्रभक्ति के भाव से सुगन्धित कर, विश्व व्यापी नारी संगठन के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा।

वंदनीय मौसी जी का चिंतनशील व्यक्तित्व एवम् दूरदर्शी विचारधारा का ही परिणाम था कि उन्होंने लाखो महिलाओं को संगठन का महामंत्र दिया। मातृशक्ति को राष्ट्र कार्य के लिए प्रेरित कर ऐसा विश्व व्यापी नारी संगठन को साकार रूप प्रदान किया। अपने स्वयं के विचारो से ध्येय तोरण के रंग भर के संगठन का चौखट स्वयं तैयार किया। सांसारिक दायित्व,राष्ट्र चिंतन के साथ साथ उनका मन धर्म तथा आध्यात्म में भी रमा रहता था।

वंदनीय मौसी जी महिलाओं के साथ रामायण पाठ किया करती थी तथा युवा पीढ़यों तक रामायण , महाभारत के प्रेरक प्रसंगों को तत्कालीन परिस्थितियों से जोड़ कर प्रवचनों के माध्यम से पहुंचाया करती थीं। वे कहा करती

थीं कि जिस घर में माता सीता रहती है, राम जी स्वयं वहां चले आते हैं, माता सीता से ही प्रभु श्री राम की संपूर्णता है। वंदनीय मौसी जी धर्मो रक्षति रक्षितः के विचार पर विश्वास रखती थीं, वे कहती थीं धर्म कितना भी अच्छा क्यों न हो, रक्षण के बिना व्यवहारिक क्षेत्र में नहीं टिक सकता। इसलिए हमें धर्म परायण तथा धर्म का अनुयायी होना चाहिए। वंदनीय मौसी जी राष्ट्र चिंतन में डूबी रहती थीं। सुशीला, सुधीरा के साथ स्त्री समर्थ भी हों ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के विचार उनके मन में अंकित थे कि जिस तरह गरूड़ पक्षी अपने उड़ान भरता है तो उसके दोनों पंख सामर्थ्य शाली होने चाहिए ।ठीक वैसे ही स्त्री राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र को सामर्थ्यवान तथा सक्षम बनाने के लिए स्त्री को भी समर्थ तथा सक्षम होना चाहिए। और उनका यह चिंतन सार्थक हुआ जब उन्होने 1936 विजयादशमी के परम पावन दिन राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की।

वंदनीय मौसी जी का कैसा अचल अडिग आत्म विश्वास रहा होगा, जो उन्होंने राष्ट्र की स्त्रियों में इस संकल्प दीप को न केवल प्रज्वलित किया बल्कि निरन्तर जगाए रखा। उन्होंने आत्म रक्षा जैसे विषय पर जहां नारियों को अबला समझा जाता रहा है, आत्म रक्षण के शारीरिक प्रशिक्षण को समिति के शिक्षण वर्गो में समावेश किया। स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा योगासन के महत्व को जानकर स्वयं योगासन सीख कर समिति के वर्गो में इसका समावेश किया। वंदनीय मौसी जी का कैसा साहसी व्यक्तित्व रहा होगा, जो 13 अगस्त 1947 को जब भारत पाकिस्तान का औपचारिक बंटवारा होने के मात्र एक दिन शेष था। तब पकिस्तान जा कर न केवल स्वयं के साहस का परिचय दिया बल्कि वहां रह रही हिन्दू बहनों का हौसला बढाया और 1200 सेविकाओं की एक सभा करके उनमें हिम्मत जगाई, उनके सुरक्षित भारत पहुंचने की योजना बनाई। इस प्रकार अपने संकल्प से उन्होंने असम्भव कहे जाने वाले कार्यों को साकार कर दिखाया। वंदनीय मौसी जी के जन्मदिवस को राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाएं संकल्प दिवस के रूप में मनाती है।

वर्ष भर के लिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संकल्प ले कर पूरे निष्ठा से पूर्ण करती है। आज उनके द्वारा स्थापित संगठन राष्ट्र सेविका समिति द्वारा महिलाओं के नैसर्गिक गुणों का संवर्धन और शक्ति के अपार पुंज को सफतापूर्वक अनवरत जागृत रखा जा रहा है। समिति देश, विदेश, ग्राम, शहर, कस्बों में साप्ताहिक तथा दैनिक अंतराल में शाखा लगाती है। इन शाखाओं में सेविकाओं के शारीरिक, बौद्धिक, आत्मरक्षा, मनोबल आदि के लिए उपक्रम किए जाते हैं। समिति प्रत्येक वर्ष अपने सूत्र स्त्री राष्ट्र की आधार शिला है के साथ शिविरों का आयोजन बालिकाओं तथा गृहणी सेविकाओं के लिए अलग अलग स्तरों पर करते है। साथ ही आरोग्य शिविरों, उद्योग मंदिरो, बाल मंदिरो एवम् संस्कार वर्ग1 सहित सेवा कार्य करते हैं।

आज राष्ट्र सेविका समिति अपने ध्येय वाक्य *तेजस्वी हिन्दू राष्ट्र के पुनर्निर्माण* की ओर अग्रसर भारत का सबसे बड़ा महिला संगठन है। समिति महिला छात्रावासो, निःशुल्क चिकित्सा केंद्रो, लघु उद्योगों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, साहित्य केंद्रो एवम् संस्कार केंद्रो, गरीब बालिकाओं के लिए निःशुल्क ट्यूशन आदि संचालित करती है, अनेक शिक्षण, स्वास्थ्य तथा स्वावलंबन संस्थान चला कर विशेष रूप से समाज के पिछड़े तथा वनवासी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अनाथ बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास और पड़ाई की व्यवस्था भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। यह सब उस परम तेजस्वी, दृढ़ संकल्पित पुण्यात्मा की ही प्रेरणा से संपन्न हो रहा है, जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति स्वरूप सबकी मां सी बन गईं वंदनीय मौसी जी।

यया राम यशोगानैः कृता भारत जागृतिः।
लक्ष्मी केलकरोपाख्याम स्मरामो मवाशी वयं ।।

चीन के सामने क्या हैं मुश्किलें

चंद्रभूषण

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का थर्ड प्लेनम चर्चा में है। 15 से 18 जुलाई तक चलने वाली चीन की इस महत्वपूर्ण नीति निर्धारक कवायद में उसकी सीमा से बाहर बैठे पॉलिसी मेकर्स की भी खासी दिलचस्पी है। अभी वहां बेरोजगारी सामान्य से ज्यादा है और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र संकट का सामना कर रहे हैं। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के अलावा भारत-चीन सीमा पर भी तनाव बना हुआ है। ऐसे में आगे की दिशा को लेकर चीन पर सबकी नजर है।

प्लेनम को हिंदी में 'पूर्णाधिवेशन' कहा जाता रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अलावा बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले अन्य पार्टी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की दो कांग्रेसों के बीच होने वाले कुल पांच पूर्णाधिवेशनों में 'तीसरा' एक रवायत की तरह सबसे खास होता आया है। तंग श्याओफिंग ने 1978 में चीन के आधुनिकीकरण की घोषणा ऐसे ही एक 'थर्ड प्लेनम' में की थी और 1993 में चीनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया था। शी चिनफिंग को भी सबसे ज्यादा 2013 में की गई उनकी थर्ड प्लेनम घोषणाओं के लिए ही याद किया जाता है। कायदे से यह प्लेनम पिछले साल अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। इसके आयोजन में हुई देरी से तमाम अटकलें पैदा हुई हैं।

कुछ तथ्यों पर नजर डालें। कोविड को लेकर चीन ने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती और अर्थव्यवस्था को खोलने में देर कर दी। इससे महामारी में उसकी लय एक बार बिगड़ी तो पूरी तरह सम पर आज भी नहीं आ पाई है। 2023 में उसकी जीडीपी ग्रोथ 4.6% दर्ज की गई। जितनी ऊंची जीडीपी हम वहां देखते आए हैं, उसके मद्देनजर यह काफी कम है।

रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट का हाल बुरा बताया जा रहा है। उपभोक्ता सामानों का बाजार ठहरा हुआ है। सबसे

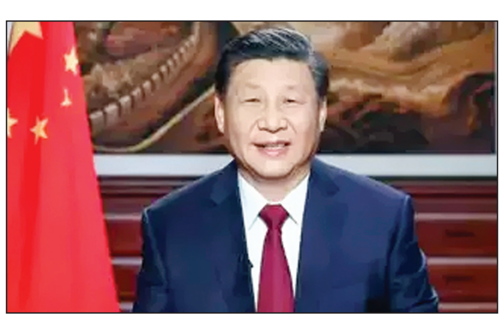

बड़ी समस्या निवेश के स्तर पर देखी जा रही है। चीन में निजी और सरकारी उद्यमों का अनुपात 60 और 40 का है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का निवेश पिछले एक साल में बढ़ना तो दूर, 0.4% कम हो गया है। विदेशी निवेश 8% नीचे आ गया है।

चीन की शहरी नौकरियों में 80% निजी क्षेत्र से ही आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में निवेश का न आना रोजगार पर बुरा असर डाल रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत को सीधे तौर पर कोरोना की बंदी से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ भूमिका शी चिनफिंग की नीतियों की भी रही है। 2012 की पार्टी कांग्रेस में पार्टी महासचिव पद पर उनके चुनाव को भ्रष्टाचार, असमानता और चीनी अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के दबदबे के खिलाफ जनादेश की तरह प्रस्तुत किया गया था। इसी समझ पर चलते हुए उन्होंने एक रेलमंत्री, एक गवर्नर और एक के बाद एक, कुल दो रक्षा मंत्रियों को उनके पदों से बर्खास्त करके उन पर मुकदमा चलवाया और सख्त से सख्त सजाएं दिलाईं। चीन के बौद्धिक उद्यमी के रूप में मशहूर जैक मा और उनके ऐंट ग्रुप पर पड़े चीनी हुकूमत के हथौड़े को भ्रष्टाचार के बजाय उनके 'अति-आत्मविश्वास' को दंडित करने की तरह पेश किया गया। विदेशी निवेश पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। एवरग्रैंड ग्रुप का डूबना चीन में रियल एस्टेट सेक्टर के संकट का बड़ा नमूना था। ऐसी कंपनियों और उन्हें कर्ज देने वाले बैंकों के दिवालिया होने का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ इलाकों में प्रदर्शन कर रहे घर खरीदारों के खिलाफ टैंक तक भेजने पड़ गए।

नए चीन के प्रतीक पुरुष तंग श्याओफिंग की घोषित नीति थी, 'बिल्ली जब तक चूहे पकड़ती है तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काली है या सफेद।' तात्पर्य यह कि देश में समृद्धि आए, लोगों में खुशहाली की उम्मीद जगे तो इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन से तरीके इसके लिए अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस नीति पर चलते हुए 2015 आते-आते हाल ऐसा हो गया कि दोहरी कमाई वाले एक शहरी मिडिल क्लास परिवार के लिए भी अपने अकेले बच्चे की अच्छी परवरिश, बढ़िया शिक्षा मुश्किल हो गई। ऐसे में सबसे सख्त कार्रवाई चीनी हुकूमत ने ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के खिलाफ की।

पश्चिमी मीडिया ने इसे एक तुगलकी कदम के रूप में पेश किया। थर्ड प्लेनम को लेकर वहां छप रही टिप्पणियों में यह बात बार-बार आ रही है कि शी चिनफिंग को आगे ऐसी हरकतों से बाज आने का कोई संकेत यहां जरूर देना चाहिए। इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि अपने यहां रोजगारपरक क्षेत्रों में पूंजी लगाने और उपभोक्ता खर्चे बढ़ाने के बजाय चीन का सारा जोर तकनीकी के ऐसे क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है, जो सुदूर भविष्य में ही आम लोगों के काम आ सकेंगे।

थर्ड प्लेनम में चर्चा के लिए प्रस्तुत परिपत्र में बातें तो सारी गोलमोल-सी ही हैं, लेकिन उसमें सन 2035 तक 'एडवांस्ड सोशलिस्ट इकॉनमी' हासिल करने के लक्ष्य को लेकर एक दृढ़ता भी है। तंग श्याओफिंग सन 2050 तक चीन में किसी तरह का लोकतांत्रिक समाज बना लेने की बात करते थे। इस तरह का कोई दिशा संकेत जब पार्टी कांग्रेसों में ही नहीं दिख रहा तो प्लेनम में क्या दिखेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर और विदेशी पूंजी के लिए कानून और प्रशासन के स्तर पर आसानी पैदा करने के कुछ सुराग इसमें जरूर नजर आते हैं।

सुनक की प्रतिक्रिया मोदी के बिल्कुल विपरीत थी

जूलियो रिबैरो

पिछले सप्ताह यूनाइटेड किंगडम में संसद के लिए हुए चुनावों में ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। हार के बाद भी वह विनम्र थे। उन्होंने कहा, ''मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। मैं कई अच्छे, मेहनती उम्मीदवारों की हार की जिम्मेदारी लेता हूं।'' अपेक्षित परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी में शीर्ष पद के लिए अन्य महत्वाकांक्षी राजनेताओं के लिए मैदान खाली हो गया। मुझे यकीन है कि सोचने और महसूस करने वाले भारतीयों की नजर और कम से कम मेरी नजर में ऋषि का कद और कई पायदान ऊपर चला गया। मेरे मन की आंखों में मैंने हार पर उनकी प्रतिक्रिया की तुलना हमारे अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया से की, जब उनकी पार्टी ने लोकसभा में अपनी पिछली 303 सीटों में से 60 सीटें खो दी थीं। मोदी ने इस बार 400 सीटें जीतने का दावा किया था। उन्होंने देश भर में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, अपने भ्रमणशील उत्साह में देश के कोने-कोने का भ्रमण किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन अकेले ही किया। उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश का अपना गढ़ खो दिया और आश्चर्य की बात यह है कि वह फैजाबाद सीट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से हार गए। मोदी ने बिना पलक झपकाए अपना प्रिय तीसरा कार्यकाल जारी रखा। उनके लिए यह हमेशा की तरह काम था। गौमांस खाने वालों और मवेशियों का व्यापार करने वालों की लिंचिंग के साथ-साथ विभिन्न अपराधों के आरोपी मुसलमानों के घरों और दुकानों को गिराना भाजपा शासित राज्यों में जारी रहा। उन्होंने लोकसभा चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन पर कोई निराशा नहीं जताई और न ही अपनी पार्टी के सदस्यों को इस बात के लिए कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत समझी। इसे उनकी व्यक्तिगत विफलता ही कहा जा सकता है क्योंकि भाजपा ने उनके नाम पर चुनाव लड़ा था। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनके परिवार की जड़ें पंजाब में हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। उनकी जड़ें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में हैं। वे नरेंद्र मोदी और लाखों भारतीयों की ही तरह हैं। फिर भी, अपने करियर में एक झटके पर सुनक की प्रतिक्रिया मोदी के बिल्कुल विपरीत थी। ऋषि सुनक एक धार्मिक हिंदू हैं। यह स्पष्ट है कि वह अपने धर्म के सार का पालन करते हैं। वह विनम्र और पश्चातापी थे। उन्होंने हार के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। आर.एस.एस. को उनके व्यक्तित्व और व्यवहार के इस पहलू पर टिप्पणी करनी चाहिए जैसे उसने मोदी का नाम लिए बिना की थी। आखिरकार, दुनिया के सभी महान धर्मों की मूल शिक्षाएं समान हैं। वे सभी विनम्रता सिखाते हैं और अहंकार को अस्वीकार करते हैं। वे झूठ को अस्वीकार करते हैं। वे बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के करुणा और सेवा का उपदेश देते हैं। फिर, हमारे 'देसी' राजनेता हमारे अपने रिश्तेदारों से अलग क्यों हैं जो दूसरे देशों में चले गए हैं और वहां उन्होंने अविश्वसनीय मान्यता प्राप्त की है? ऋषि सुनक उस देश के प्रधानमंत्री बने जिसने हम पर 2 शताब्दियों या उससे अधिक समय तक शासन किया। कमला हैरिस, जिनकी मां का परिवार तमिलनाडु से अमरीका चला गया था, आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की उप-राष्ट्रपति हैं। पश्चिम में बेहतर जीवन स्तर की तलाश करने वाले भारतीयों के अलावा, दुनिया के छोटे देशों में भी भारतीय मूल के नागरिक हैं।

क्या हिंदू धर्म में हैं 33 करोड देवी-देवता

हिंदू धर्म के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ऐसे में कुछ खास और गूढ जानकारियों को हम आपके साथ बांट रहे हैं

देवभाषा संस्कृत में कोटि के दो अर्थ होते है, कोटि का मतलब प्रकार होता है और एक अर्थ करोड़ भी होता। हिन्दू धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए ये बात उडाई गयी है कि हिन्दुओ के 33 करोड़ देवी देवता हैं। विद्वानों के अनुसार कुल 33 प्रकार के देवी देवता हैं हिंदू धर्म में - 12 प्रकार हैं आदित्य- धाता, मित, आर्यमा, शक्रा, वरुण, अँश, भाग, विवास्वान, पूष, सविता, तवास्था, और विष्णु...! 8 प्रकार में हैं वासु-, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। 11 प्रकार हैं- रुद्र, हर, बहुरुप,त्रयँबक,अपराजिता, बृषाकापि, शँभू, कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा, और कपाली एवं दो प्रकार हैं अश्विनी और कुमार। कुल- 12+8+11+2=33

भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ और भी जानना उचित रहेगा-

दो पक्ष- कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष।
तीन ऋण -देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण।
चार युग - सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग
चार धाम - द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम धाम
चारपीठ - शारदा पीठ (द्वारिका), ज्योतिष पीठ (जोशीमठ बद्रिधाम), गोवर्धन पीठ (जगन्नाथपुरी), श्रन्गेरिपीठ!
चार वेद- ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद! चार आश्रम - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास!
चार अंत :करण - मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार!
पंच गव्य - गाय का घी, दूध, दही,गोमूत्र, गोबर!
पञ्च देव - गणेश, विष्णु, शिव, देवी,सूर्य!
पंच तत्त्व - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश!
छह दर्शन - वैशेषिक, न्याय, सांख्य,योग, पूर्व मिसांसा, दक्षिण मिसांसा!
सप्त ऋषि - विश्वामित्र, जमदाग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्री, वशिष्ठ और कश्यप!
सप्त पूरी -अयोध्यापूरी,मथुरा पूरी, माया पूरी (हरिद्वार), काशी, कांची (शिन कांची - विष्णु कांची), अवंतिका और द्वारिका पूरी!
आठ योग - यम, नियम, आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधी !
आठ लक्ष्मी - आग्घ, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी!
नव दुर्गा -शैल पुत्री, ब्रह्मचारिणी,चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री!
दस दिशाएं - पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इशान, नेऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश एवं पाताल!
मुख्य 11 अवतार - मत्स्य, कच्छप, वराह,नरसिंह, वामन, परशुराम,श्री राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध, एवं कल्कि!
बारह मास - चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन!
बारह राशी - मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कन्या।
बारह ज्योतिर्लिंग - सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, बैजनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घुष्नेश्वर,भीमाशंकर, नागेश्वर।
पंद्रह तिथियां- प्रतिपदा,द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी,दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावष्या!
19 स्मृतियां - मनु, विष्णु, अत्री, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगीरा, यम, आपस्तम्ब, सर्वत, कात्यायन, ब्रहस्पति, पराशर, व्यास, शांख्य, लिखित, दक्ष, शातातप, वशिष्ठ!

मंगलवार व शनिवार को करें इन मंत्रों का जाप

हनुमानजी करेंगे हर समस्या का समाधान

मंगलवार और शनिवार को रामभक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है। इन दोनों दिन हनुमान जी का व्रत व पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि मंगलवार के दिन व्रत किया जाए तो मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है। यहां कुछ मंत्रों के बारे में बताया गया है जिनके जाप मात्र से व्यक्ति की विवाह, विद्या व रोग संबंधी सभी समस्याओं का हल हो जाता है।

इस मंत्र का जाप करने से विद्यार्थियों की बल बुद्धि में बढ़ौत्तरी होती है।

बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं हरहु कलेश विकार।

व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा या रोग है तो मंगलवार या शनिवार के दिन इस मंत्र के जाप मात्र से निवारण हो जाएगा।

हनुमान अंगद रन गाजे हांक, सुनत रजनीचर भाजे।

लड़की या लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन इस मंत्र का जाप करें। इससे विवाह शीघ्र होने के योग बनते हैं।

मास दिवस महुं नाथु न भावा, तो पुनि मोहि जिअत नहि पावा।

घर में सुख शांति के लिए आजमाए ये सरल उपाय

हर इंसान चाहता है कि मेरे घर में सुख-शांति हमेशा बनी रही। लोग बहुत परेशान होते हुए भी कुछ नहीं समझ पाते की हमें अब क्या करना चाहिए। खबर यह है कि गृहस्थ व्यक्ति हमेशा कामना करता है कि उसके घर मे शांति हो, लेकिन उसके प्रयासों के बाद भी कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है, जो उसके मन को अशांत कर देती है ऐसे में उसके कारणों की खोज परोक्ष रूप में करनी चाहिए। लहसुन की गांठ घर में रखने से सर्प कभी घर में प्रवेश नहीं करता। जो व्यक्ति यह समझता है कि घर के लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि वह हमेशा उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि वह हमेशा सही होता है। ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से जल में थोड़ा-सा गुड मिलाकर निम्मलिखित मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपके घर में प्रतिदिन कभी भी किसी भी चीज की संपन्नता स्थिर नहीं रह पाती है तो अपने घर में महालक्ष्मी शंख को रखें, शाम में यंत्र को एकटक निहारते हुए श्रीं श्रीयेयै नमः का नियमित जप करें। जितनी अधिक संख्या में कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है। यदि आपके घर में प्रतिदिन कोई न कोई मुसीबत आती है और आपको लगात है कि कोई आप पर तंत्र-मंत्र करवाता है तो आप किसी भी शुक्लपक्ष के सोमवार को नवदुर्गा यंत्र को घर के मुख्य द्वार पर लगाकर रोज 21 बार ऊँ ह्रीं दुर्गायै नमः का नियमित जप करें। गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को गत्ते पर लाल स्याही से लिखकर टांग देने से घर की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिस घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्रीसूक्त या श्रीलक्ष्मी सूक्त पाठ होता है। उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है।

गाय कैसे और क्यों करती है वास्तु दोषों का निवारण

वास्तु के अनुसार अगर भवन, घर का निर्माण करना हो यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को लाकर बांधा जाए तो वहां संभावित वास्तु दोषों का स्वतः निवारण हो जाता है। वह कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आतीं। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हैं। 'समरांगण सूत्रधार' जैसा प्रसिद्ध वृहद् वास्तु ग्रंथ गो रूप में पृथ्वी-ब्रह्दि के समागम-संवाद से ही आरंभ होता है। वास्तुग्रंथ 'मयमतम' में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो सवत्सा या बछड़े वाली हो। शास्त्रों में लिखा हैं की जब नवजात बछड़े को जब गाय दुलारकर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तुप्रदीप, अपराजितपृच्छा आदि में भी आई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेती है, उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है-

निविष्टं गोकुलं यत्र श्वांस मुंचति निर्भयम।
विराजयति तं देशं पापं चास्याप कर्षति॥

यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा हो, वहां पुत्र-पौत्र, धन, विद्या, सुखादि जो भी चाहिए, मिल सकता है। यही मान्यता अत्रिसंहिता में भी आई है। अत्रि ने तो यह भी कहा है कि जिस घर में सवत्सा धेनु नहीं हो, उसका मंगल-मांगल्य कैसे होगा?

गाय का घर में पालन करना बहुत लाभकारी है। ऐसे घरों में सर्वबाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। जिस घर में गाय रहती है उसमें रहने वाले बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्रीकृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद दंपती ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नजर उतारी और भय का निवारण किया। सवत्सा गाय के शकुन लेकर जाने से कार्य सिद्ध होता है। पद्मपुराण, और कूर्मपुराण में कहा गया है कि कभी गाय को लांघकर नहीं जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार, उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रंभाने की ध्वनि कान में पड़ना शुभ है। संतान लाभ के लिए घर में गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है। शिवपुराण व स्कंदपुराण में कहा गया है कि गो सेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। गाय के पांव की धूली का भी अपना महत्व है। यह पाप विनाशक है, ऐसा गरुड़पुराण और पद्मपुराण का मत है।

क्लेशों से मुक्ति दिलाता विश्रांति घाट

श्री कृष्ण ने स्नान कर किया था विश्राम

ततो विश्रांति तीर्थाख्यं तीर्थमहो विनाशनम। संसारमरू संचार क्लेश विश्रांतिदं नृणाम।

संसार रूपी मरूभूमि में भटकते हुए, त्रितापों से पीड़ित हर तरह से निराश्रित, विविध क्लेशों से क्लांत होकर जीव श्री कृष्ण के इस महातीर्थ में स्नान कर विश्राम अनुभव करता है इसलिए इस तीर्थ का नाम विश्रांति या विश्राम घाट है। विश्राम घाट की संरचना दो-मंजिली है। इसे बनाने के लिए लखोरी ईंट व चूने, लाल एवं बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। घाट को बुर्ज व खंभों पर बने अर्द्ध-गोलाकार, कांटेदार मेहराबों से सुसज्जित किया गया है। घाट का मध्य क्षेत्र खिले हुए आकर्षक रंगों से सजा हुआ है। यह तीन तरफ से मठों से घिरा हुआ है व चौथी तरफ सीढियां नदी में उतर रही हैं। मध्य क्षेत्र में संगमरमर से निर्मित श्री कृष्ण व बलराम की मूर्तियां नदी की ओर मुख करके स्थापित हैं। मूर्तियों के सामने पांच विभिन्न आकार के मेहराब हैं। बीच का मेहराब पत्थर के कुर्सी आधार व पत्थर के छोटे स्तंभ से निर्मित आयताकार है, जबकि नदी की तरफ वाले मेहराब ऊपरी मंजिल का सहारा लेकर छतरी की आकृति बनाते हैं। यहां अनेक संतों ने तपस्या की एवं अपना विश्राम स्थल बनाया। उक्त घाट पर भारत के धर्मभीरू राजाओं ने तुलादान (एक पलड़े में स्वयं व दूसरे में अपने वजन के सोना-चांदी जवाहरात) किए थे। तुला को लटकाने के मेहराब आज भी लगे हैं। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। दक्षिण दिशा के घाटों पर समाधियां जिनमें शंकरजी के मंदिर हैं। ये समाधियां सिंधिया परिवार से संबंधित हैं। देखभाल के अभाव में उक्त समाधियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गई हैं। उत्तर दिशा के घाटों में गणेशतीर्थ घाट है, चक्रतीर्थ, कृष्णगंगा, स्वामीघाट, असिकुंड तीर्थ आदि हैं। जब शिवाजी महाराज आगरा किले से औरंगजेब की कैद से निकले तब मां जगदंबा (महाविद्या) की पूजा-अर्चना करके स्वर्ण छत्र चढ़ाया। तत्पश्चात गणेशजी का पूजन कर सीधे महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान किया। गणेशजी व मां जगदंबा के मंदिर आज भी उक्त स्थलों पर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इस स्थान पर विश्राम किया था इसलिए यहां की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने महाबलशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसका अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु-बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। किंतु भगवान से भूले-भटके जन्म-मृत्यु के अनंत, अथाह सागर में डूबते-उबरते हुए क्लांत जीवों के लिए यह अवश्य ही विश्राम का स्थान है।

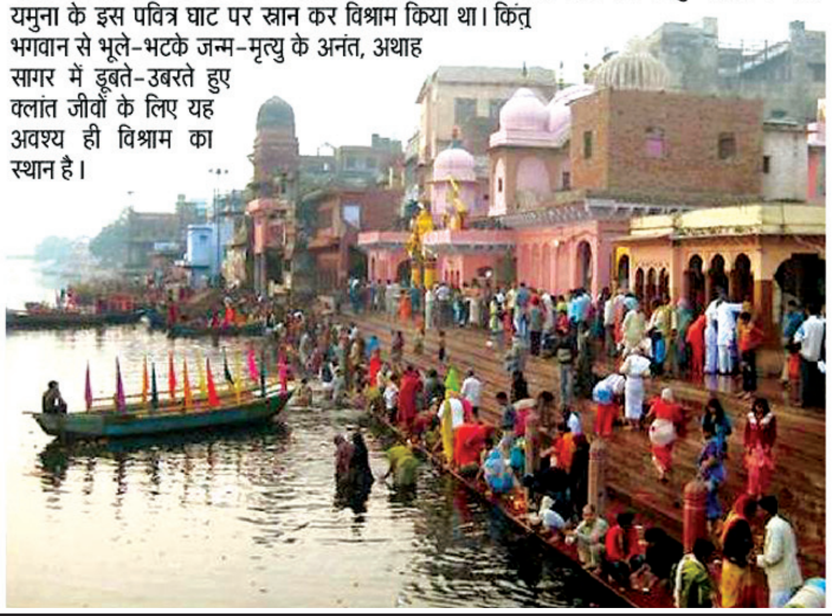

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

योगी ने भी माना हमारा अति आत्मविश्वास महंगा पड़ा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर यह है स्वीकार किया कि अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाई है। जो विपक्ष पहले हार मान के बैठ गया था, वो आज फिर से उछल-कूद मचा रहा है। योगी ने यह है बातें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में कही। हार के कारण गिनाते समय योगी ने यह बात स्पष्ट नहीं किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन उन्होंने संकेतों में बहुत कुछ कह दिया। सवाल यह है कि क्या योगी दिल्ली से निकले 400 पार के नारे से पर आपत्ति जता रहे हैं या फिर केंद्र ने जिस तरह से प्रत्याशी बदलने के उनकी स्कीम को अमली जामा नहीं पहने दिया उससे वह नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी की हार का जो सबसे बड़ा कारण गिनाया जा रहा है उसमें यही कहा जा रहा है भाजपा अपने कर्मो से हारी है। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में योगी ने कहा कि आज आपके सहयोग से हमें प्रदेश को माफिया मुक्त करने में सफलता मिली है।

अतीत में जाने का क्या मतलब हमने गलती मानी: पी चिदंबरम

नईदिल्ली। संविधान हत्या दिवस को लेकर राजनीति जारी है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। इन सबसे बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आपातकाल एक गलती थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के पहले ही तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया था। पी चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी 18वीं या 17वीं सदी में वापस क्यों नहीं जा रही है? आज रहने वाले 75 फीसदी भारतीय 1975 के बाद पैदा हुए हैं। आपातकाल एक गलती थी और इसे इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था। हमने संविधान में संशोधन किया है ताकि आपातकाल इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता।

आप के आरोप पर तिहाड़ प्रशासन का आया जवाब

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा पर हमलावर है। आप का आरोप है कि भाजपा केजरीवाल को जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है और मधुमेह रोगी होने के कारण उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना अपराध है। जेल प्रशासन कई बार दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुका है। वहीं,, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित निराधार आरोप लगा रहे हैं और स्पष्ट किया कि जेल में रहने के दौरान उनके रक्तचाप और शर्करा के स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी। सेंट्रल जेल नंबर 2 के अधीक्षक के कार्यालय के अनुसार, केजरीवाल अदालत के आदेशों के अनुसार, घर का बना खाना सहित चिकित्सकीय रूप से निर्धारित आहार का पालन कर रहे हैं।

मनीष सिसोदिया को फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत

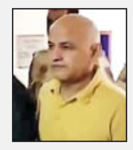

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (15 जुलाई) को शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट 22 जुलाई को सीबीआई मामले की अगली सुनवाई करेगी। सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें मार्च 2023 में अब खत्म हो चुकी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने बार-बार खंडन किया।

मोदी ने नेपाल के नए पीएम केपी शर्मा ओलीको बधाई दी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली को बधाई दी, जिन्हें रविवार को चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा- नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर @केपी शर्मा ओली को बधाई। हम दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने तथा हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। रविवार शाम को, इस अवसर पर सजे-धजे केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल हासिल करने के बाद बालकोट स्थित अपने आवास के बाहर समर्थकों की एक उत्साही भीड़ का स्वागत किया। उनकी नियुक्ति तब हुई, जब निवर्तमान पीएम पुष्प कमल दहल सदन में बहुमत परीक्षण के दौरान प्रतिनिधि सभा का विश्वास हासिल करने में विफल रहे।

विदेशी ताकतों ने पहुंचाया भाजपा को नुकसान: शिवराज

लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान, कांग्रेस को बताया झूठ बोलने की मशीन

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी हलचल मची हुई है। दरअसल, राजस्थान में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि विपक्ष के बीच कुछ %विदेशी हाथ% सक्रिय हैं, जो नहीं चाहते कि भाजपा किसी भी तरह चुनाव जीते। जयपुर में राज्य भाजपा कार्यसमिति की बैठक में बोलते हुए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा हमारे विरोधी - जिस में ये सच है कि विदेशी ताकतें भी शामिल हैं - ये हमारे देश में कैसे भी बीजेपी की सरकार ना रहे इसकी कोशिश करते है।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, ये हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई ताकतें किसी भी कीमत पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। विपक्षी कांग्रेस को झूठ बोलने की मशीन बताते हुए चौहान ने तर्क दिया कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि तब कुछ शक्तियों ने हस्तक्षेप किया था।

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में अपने संबोधन में शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कथित तौर पर यह दावा करने के लिए कि हिंदू बहुत हिंसक हैं, राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि यह बचकानी मानसिकता को दर्शाता है। चौहान ने दावा किया कि विदेश में बैठी कुछ विदेशी ताकतें जिनके हितों को ईमानदार नीतियों के कारण नुकसान हो रहा है, वे उत्सुक हैं कि पुरानी सरकार जैसी सरकार बने।

राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे ने चौहान की बात दोहराई और कहा कि यह उन कारकों में से एक हो सकता है जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या में कमी आई। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यह पहली राज्य कार्यसमिति की बैठक थी। बैठक में लगभग 8000 भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राज्य की कुल 25 में से 11 सीटों की हार का विश्लेषण करते हुए, सहस्रबुद्धे ने कहा कि पार्टी को लोकसभा में लगभग 65 सीटों का नुकसान हुआ है और पार्टी आत्मनिरीक्षण अभियान पर है क्योंकि सभी को गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

बजट सत्र से पहले राज्यसभा में कम हुई भाजपा की ताकत

नईदिल्ली। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ताकत चार मनोनीत सदस्यों के शनिवार को सेवानिवृत्त होने के बाद 86 हो गई, जो पार्टी का हिस्सा थे, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटें 101 रह गईं। 245 सदस्यीय उच्च सदन में 19 रिक्तियों के कारण वर्तमान सदस्यों की संख्या 226 है। राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी ने शनिवार को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। सभी चार निवर्तमान सांसदों को भाजपा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा गुटनिरपेक्ष सदस्यों के रूप में चुना गया और बाद में औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ गठबंधन किया गया।

इसके साथ, सत्तारूढ़ गठबंधन की वर्तमान ताकत 113 के बहुमत के निशान से नीचे चली गई है। लेकिन यह अभी भी सात गुटनिरपेक्ष सदस्यों, दो निर्दलीय सदस्यों और एआईएडीएमके जैसे मित्र दलों के समर्थन से बजट के सदन में महत्वपूर्ण कानून पारित कर सकता है। केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। मौजूदा सदन में ऐसे सात सांसदों ने खुद को गुटनिरपेक्ष (भाजपा का हिस्सा नहीं) रखा है लेकिन ऐसे सदस्य किसी भी प्रस्ताव या कानून को पारित करने में सत्ताधारी दल का पक्ष लेते रहे हैं।

हालाँकि, सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की दूसरों पर निर्भरता को कम करने के लिए नामांकित श्रेणी के तहत रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए। वर्तमान सदन में 19 रिक्तियां हैं जिनमें जम्मू-कश्मीर और नामांकित श्रेणी से चार-चार, और आठ अलग-अलग राज्यों से 11 (असम, बिहार और महाराष्ट्र से दो-दो और हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से एक-एक) शामिल हैं।

11 सीटों में से 10 पिछले महीने लोकसभा चुनाव के कारण खाली हुई थीं जबकि एक सीट भारत राष्ट्र समिति के सदस्य के केशव राव के कांग्रेस में शामिल होने के कारण खाली हुई थी। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के पास वर्तमान में उच्च सदन में 87 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 26 और तृणमूल कांग्रेस के पास 13 सीटें हैं। दिल्ली और तमिलनाडु में सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सीटें हैं।

नईदिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पांच महीने जेल में बिताने और जेल से रिहा होने तथा फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस चुनावी मौसम के बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है।

चुनाव बाद भी यात्रा मोड में क्यों हैं राहुल गांधी?

नईदिल्ली। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटें क्या आई, उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के कार्यशैली में बड़ा बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेता के तौर पर पदभार संभालने के बाद राहुल गांधी की जमीनी सक्रियता लगातार जारी है। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े चुनाव के बाद नेता कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। संसद के उद्घाटन सत्र में ही उन्होंने बता दिया कि इस बार उनकी भूमिका अलग रहने वाली है। जो कि कहीं ना कहीं भाजपा को टेंशन में ला रही होगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया और दिल्ली में सक्रियता के अलावा राहुल गांधी दूरदराज के इलाकों में भी जा रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच गए जहां एक भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट की एक समूह से मुलाकात कर ली। उनकी समस्याओं को जाना और इस बहाने सरकार पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। राहुल गांधी गुजरात दौरे पर भी गए जहां उन्होंने पार्टी कार्यक्रम के अलावा राजकोट अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की।

इतना ही नहीं राहुल गांधी असम और मणिपुर भी पहुंच गए। असम में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की जबकि मणिपुर में राहुल ने राहत शिविरों का दौरा किया और केंद्र की मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे। राहुल लगातार प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वह राज्य में हिंसा भड़कने के बाद तीसरी बार पहुंचे थे लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंचे जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की। राहुल और कांग्रेस को लग रहा है कि जनीन पर संघर्ष के साथ ही उनकी पार्टी

एर बार फिर उभर सकती है।

राहुल गांधी की जमीनी सक्रियता को देखें तो ऐसा लगता है 99 सीटों से कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी मिली है जिसकी बदौलत पार्टी एक बार फिर से उभरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमें खत्म करने की बात कर रहे हैं वह कमजोर हो चुके हैं। हमें जमीन पर मेहनत करनी चाहिए और पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ उभर सकती है। राहुल गांधी अपने भीतर के जुझारूपन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे। यही कारण है कि गुजरात जैसे राज्य का दौरा करने के दौरान वह दावा कर रहे हैं कि हम यहां भी भाजपा को हराने जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत छोड़ो न्याय यात्रा की बदौलत देश की जमीनी हकीकत को समझा। इन दोनों यात्राओं ने उन्हें जमीन का नेता बनने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को अब लगने लगा है कि एकजूटता और जमीनी लड़ाई के आधार पर भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है। इसका बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे हैं। राहुल गांधी ही थे जिन्होंने लगातार इंडिया गठबंधन की वकालत की। मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने गठबंधन को बनाए रखना जरूरी समझा।

खेल
प्रमुख समाचार

अर्जेंटीना ने जीता 16वां कोपा अमेरिका खिताब

फ्लोरिडा। लुटारो मार्टिनेज ने 111वें मिनट में गोल किया, जिससे अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर अमेरिका के मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में 2024 कोपा अमेरिका जीत लिया। यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अर्जेंटीना का 16वां खिताब है और इस तरह उन्होंने उरुग्वे को अपने इतिहास की सबसे सफल टीम के रूप में पीछे छोड़ दिया है। यह अर्जेंटीना का लगातार दूसरा कोपा अमेरिका खिताब है। इसके अलावा 2022 विश्व कप खिताब भी है जो उन्होंने दोनों के बीच जीता था। दूसरे हाफ में पैर की चोट के कारण कप्तान और ताकतवर लियोनेल मेसी को बदलना पड़ा, जो 0-0 पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों के बीच आधे घंटे के अतिरिक्त समय में अक्सर अफरा-तफरी मची रही, जैसा कि नियमित समय में भी होता था। लिएंड्रो पेरेडेस द्वारा मिडफील्ड में जीत हासिल करने के बाद इंटर मिलान के मार्टिनेज को जियोवानी लो सेल्सो से गेंद मिली। मार्टिनेज ने कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास के ठीक ऊपर शॉट लगाया और गोल किया जो विजयी गोल साबित हुआ। भीड़ की परेशानी के कारण मैच एक घंटे से अधिक देर से शुरू हुआ। बिना टिकट प्रशंसक गेट में घुस गए, जिससे स्टेडियम के विभिन्न हिस्सों में भगदड़ जैसी स्थिति और अराजक दृश्य पैदा हो गए। अतिरिक्त समय के पहले भाग में अर्जेंटीना ने बड़े पैमाने पर कब्ज़ा जमाया लेकिन कोलंबिया कहीं अधिक खतरनाक दिख रहा था। मेसी पूरे टूर्नामेंट के दौरान पैर की चोट और परेशानी से जूझते रहे और अर्जेंटीना के ग्रुप चरण के फाइनल में नहीं पहुंच सके। रविवार को पहले हाफ में उन्होंने एक शॉट का प्रयास किया था। मैदान पर जाते ही मेसी ने तुरंत अर्जेंटीना की बेंच की ओर देखा। प्रशिक्षकों के बाहर आने पर वह कई मिनट तक नीचे पड़ा रहा। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की गई और तुरंत उनके दाहिने पैर से जूता उतार दिया गया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

पीएसयू बैंकों में बढ़त से सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार कमजोर वैश्विक रुख के बावजूद सोमवार को ताजा विदेशी फंड फ्लो और भारतीय स्टेट बैंक में खरीदारी की मदद से नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 145.52 अंक या 0.18 प्रतिशत चढ़कर 80,664.86 के नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 343.2 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 80,862.54 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84.55 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 24,586.70 के ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 132.9 अंक या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 24,635.05 के नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया था। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 18 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। एसबीआई, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएंडएम और आईटीसी सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे।

सेबी 12 अगस्त को 7 कंपनियों की संपत्तियों की करेगा नीलामी

नईदिल्ली। बाजार नियामक सेबी मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, सन प्लांट बिजनेस लिमिटेड और सुमंगल इंडस्ट्रीज समेत सात कंपनियों की 19 संपत्तियों की 12 अगस्त को नीलामी करेगा। यह कदम इन कंपनियों द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से एकत्र की गई धनराशि को वसूलने के सेबी के प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, नीलामी 12 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सेबी ने सुमंगल इंडस्ट्रीज, सनहेवन एग्रो इंडिया, रविकिरण रियल्टी इंडिया, मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, पुरुषत्तम इन्फोटेक इंडस्ट्रीज, जीवन साथी ड्रीम प्रोजेक्ट्स और सन प्लांट बिजनेस तथा उनके प्रवेर्तकों/निदेशकों के खिलाफ वसूली कार्यवाही में संपत्तियों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित कीं।

अब जोमैटो-स्विगी से खाना मंगवाना हो जाएगा महंगा

नईदिल्ली। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने एक बार फिर प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 6 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। ये राशि पहले पांच रुपये प्रति ऑर्डर ली जाती थी। यानी इसमें 20 फीसदी का इजाफा किया गया है। वर्तमान में दिल्ली और बेंगलुरु में लिया जाने वाला प्लेटफॉर्म शुल्क डिलीवरी शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), रेस्तरां शुल्क और हैंडलिंग शुल्क से अलग है। उच्च प्लेटफार्म शुल्क अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। प्लेटफ़ॉर्म शुल्क खाद्य एग्रीगेटर्स को लागत नियंत्रित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अप्रैल में ज़ोमैटो ने अपना प्लेटफ़ॉर्म शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ाकर 5 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया था। ज़ोमैटो ने पिछले साल अगस्त में ?2 का प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पेश किया था और बाद में अपने मार्जिन में सुधार और लाभदायक बनने के लिए इसे बढ़ाकर रू. 3 कर दिया था।

थोक महंगाई दर 16 महीने के ऊपरी स्तर पर

नईदिल्ली। देश में थोक मुद्रास्फीति जून में लगातार चौथे महीने बढ़कर 3.36 प्रतिशत हो गई। खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों तथा विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति मई में 2.61 प्रतिशत थी। जून 2023 में यह शून्य से 4.18 प्रतिशत नीचे रही थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, '' जून 2024 में मुद्रास्फीति बढ़ने की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, कच्चे रसायन तथा प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि रही।'' आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जून में 10.87 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मई में यह 9.82 प्रतिशत थी। सब्जियों की महंगाई दर जून में 38.76 प्रतिशत रही।

चुनौतियों के बीच बेहतर कर प्रशासन के अवसर पहचानना जरूरी

पिनाकी चक्रवर्ती

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारतीय कराधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक कर सुधार रहा है। यह अब सात साल पुराना हो चुका है। एक जुलाई, 2017 को शुरू होने के बाद से इसे लेकर उम्मीदें बढ़ी ही हैं। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने कर व्यवस्था को अधिक कुशल और सरल बना दिया है। हालांकि विभिन्न संक्रमणकालीन चुनौतियों के कारण थोड़ा संदेह भी पैदा हुआ है।

अप्रत्यक्ष कर पारंपरिक रूप से सरकारों के लिए कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लंबे समय तक अप्रत्यक्ष कर को राजस्व के साधन के रूप में देखा जाता था, न कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले साधन के रूप में। नतीजतन लंबे समय तक यह पुराने ढंग से चलता रहा, जिसमें कोई सुधार न हुआ। 1970 के दशक के बाद गठित विभिन्न समितियों ने इनमें व्यापक सुधार की सिफारिश की, जिनमें से कुछ को लागू किया गया। बाद में अप्रत्यक्ष कर में कई बदलाव हुए, जो अंततः 2005 में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के रूप में सामने आए। जीएसटी उसी वैट प्रणाली का विस्तार है।

जीएसटी में तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया गया है। पूरा जीएसटी नेटवर्क इस पर निर्भर है। ई-वे बिल इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वस्तुओं की आवाजाही को कर प्रशासन की नजर में रखता है। इसके अलावा ये बिल आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटी रिटर्न में स्वतः शामिल हो जाते हैं, जिन्हें पहले मैनुअली जांचना पड़ता था। चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, तथा ई-वे बिल का प्रारूप पूरे देश में एक जैसा है, इसलिए पारगमन दस्तावेजों की जांच में लगने वाला समय घट

जाता है तथा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रक्रियाओं से पैदा होने वाली उलझन भी खत्म हो जाती है।

जीएसटी का एक लाभ यह भी है कि इससे क्षेत्रीय असमानताएं धीरे-धीरे कम हो रही हैं। चूंकि पहले ज्यादातर कर उत्पादन के आधार पर थे, इसलिए कर राजस्व का ज्यादा हिस्सा उत्पादक राज्यों द्वारा अर्जित किया जाता था। अब चूंकि जीएसटी गंतव्य पर आधारित है, इसलिए कर राजस्व उन राज्यों को मिलता है, जहां उपभोग होता है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे गरीब, उपभोक्ता राज्यों को मदद मिलती है। हालांकि जिन राज्यों को इससे राजस्व में हानि की आशंका थी, उन्हें केंद्र सरकार ने पांच साल तक मुआवजा दिया। मुआवजा बंद करने के बाद भी राज्यों के राजस्व में कोई बड़ी कमी नहीं हुई। मतलब जीएसटी राजस्व राज्यों में सुव्यवस्थित हो गया है।

हालांकि, भारतीय जीएसटी एक ऐसा मॉडल है, जो इतने बड़े कर सुधार की जटिलताओं और उनके बाद के समाधान को दर्शाता है। फिर भी कर ढांचे के कुछ पहलू जीएसटी की सरलता के वादों के विपरीत हैं। इसलिए, कई मामलों में परिणाम अपेक्षा से कम रहे हैं। जीएसटी, कर दरों और विभिन्न छूटों से संबंधित नियम अब भी बदल रहे हैं, जिससे पिछले सात वर्षों में जीएसटी के प्रदर्शन का समग्र आकलन करना कठिन है। फिर भी शुरुआती आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हालांकि जीएसटी ज्यादा व्यवसायों को कर के दायरे में लाने में सफल रहा है, लेकिन उन्हें करों का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का काम अब भी बाकी है।

जीएसटी से कर प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि छोटे व्यवसायी कुल पंजीकृत लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी उनका वास्तविक कर योगदान अपेक्षाकृत नगण्य है। तर्क दिया जाता है कि इन करदाताओं को छोड़ दिया जाए, प्रशासन को उच्च बोझ से राहत दिलाई जाए और बड़े करदाताओं को बेहतर सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए पंजीकरण सीमा को सावधानीपूर्वक निर्धारित करने की जरूरत है, ताकि अधिक लोग इसमें शामिल न हों। अन्य विशेषता यह है कि छोटे व्यवसायों का कर अनुपालन बढ़ा है। लेकिन शोध से पता चला है कि छोटी कंपनियों को अपने परिचालन में ज्यादा अनुपालन लागतों का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने पोटाकेबिन बीजापुर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर स्थित पोटाकेबिन पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विभिन्न कक्षों में पहुंचकर बच्चों से पढ़ाई, मध्यान्ह भोजन सहित मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए चर्चा करते हुए प्रतिदिन नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने की बात कही। परिसर में गड्ढों में पानी का जमाव न हो इसलिए सभी संस्थाओं में नाली निर्माण, बजरी गिट्टी, मुरूम इत्यादि से गड्ढों का भराव करने, परिसर को साफ-सुथरा रखने झाड़ियों की कटाई सहित स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अध्ययनरत विद्यार्थियों को हमेशा गर्म भोजन कराने जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई मीनू चार्ट की कड़ाई से पालन करने सहित स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

जायसवाल ने इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने हेतु निरंतर मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेकर जिला और प्रदेश का नाम रौशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री श्री जायसवाल ने बच्चों को अपने हाथों से फल वितरण कर शुभकामनाएं दी।

अमेठी में लगा नारा 'हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपना मत स्पष्ट करे : रोहरा

रायपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने उत्तरप्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र में लगे नारे भारत में यदि रहना है, या हुसैन कहना है को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और भारत विरोधी बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस पर अपना मत स्पष्ट करे। अमेठी में इस तरह के नारे लगने के बाद कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह इस तरह के मजहबी उन्माद को ठीक मानती है? अमेठी, जिसे कांग्रेस अपने परिवार की सीट बताती है, में इस तरह के नारे से कांग्रेस का असली राजनीतिक चरित्र खुलकर सामने आ गया है। रोहरा ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को भारत विरोध और मजहबी उन्माद तक ले जाकर कांग्रेस देश में न केवल अराजकता फैलाने के अपने नए सियासी एजेंडे पर काम कर रही है, अपितु यह भी साफ कर रही है कि सत्ता की लालसा में विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली तक बनने से उसे कोई गुरेज नहीं है। यह उन्मादी और घोर देशविरोधी नारा लगाने का यह दुस्साहस कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के कारण हुआ है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री रोहरा ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अमेठी के इस वाकये से कोई इत्तेफाक रखते हैं? यह जगजाहिर है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी तुष्टीकरण करके साम्प्रदायिक राजनीति की राह पर चलते रहे हैं। श्री रोहरा ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का यह खेल खेलते हुए अपने पाँच साल के शासनकाल में एक ओर भगवा ध्वज के अपमान को लेकर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को न केवल नजरंदाज किया, बल्कि राजनीतिक संरक्षण में मजहबी उन्माद की आग में पूरे प्रदेश को झुलसा दिया था, वहीं दूसरी ओर जबरिया धर्मांतरण के एजेंडे को शह देकर आदिवासियों में वर्ग संघर्ष की नौबत ला दी थी। श्री रोहरा ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर बिरनपुर में भुनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग करके हत्या के मामले में कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश सरकार ने जिस प्रकार बहुसंख्यक समाज को ही प्रताड़ित करने का काम किया था। यही कांग्रेस का मूल राजनीतिक चरित्र है और इसीलिए कभी कांग्रेसियों के मुँह से भगवान श्री राम के विरोध की बात सुनी जाती है तो कभी हिन्दुत्व और सनातन को लेकर घृणित टिप्पणियाँ सुनी जाती हैं। श्री रोहरा ने कहा कि मोदी-विरोध में अंधी हो चुकी कांग्रेस की राजनीतिक समझ पर इस कदर पाला पड़ चुका है कि वह भारत, हिन्दुत्व, सनातन के विरोध के बाद इस प्रकार के देशद्रोहपूर्ण नारों का विरोध नही कर रही।

छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंटः राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में संवाद कार्यक्रम आज

मुख्यमंत्री के समक्ष युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजन साझा करेंगे अपने विचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में 16 जुलाई को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संवाद कार्यक्रम में 'युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजन' परिचर्चा में भाग लेंगे और विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संबंध में अपनी परिकल्पनाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। संवाद कार्यक्रम के समापन सत्र दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में शामिल होकर 'युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजनों' से संवाद करेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी करेंगे।

राज्य नीति आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ सत्र स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विजन/2047 की पृष्ठभूमि, परिकल्पना और विजन डाक्यूमेंट्स तैयार करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण होगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी शुभारंभ सत्र को सम्बोधित करेंगे। सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक 'युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजनों के ग्रुप से अलग-अलग चर्चा होगी।

समापन सत्र दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ 'युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजनों के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ विजन को लेकर अपनी परिकल्पना साझा करेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परिकल्पना को साकार करने में राज्य की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को विजन डॉक्यूमेंट 'अमृतकाल- छत्तीसगढ़ विजन@2047' जारी किया जाएगा। राज्य नीति आयोग द्वारा ''अमृतकाल- छत्तीसगढ़ विजन @2047'' संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सभी विभागों, सेक्टर विशेषज्ञों से

विचार-विमर्श प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए आठ वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। लगातार बैठकें आयोजित कर विचार-विमर्श किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी विकसित छत्तीसगढ़ की उनकी परिकल्पना साझा करने के लिए आयोग द्वारा वेब-पोर्टल ''मोर सपना-मोर विकसित छत्तीसगढ़'' लिंक http://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#home भी तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में पांच राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली में सूडा और चार नगरीय निकायों को 18 जुलाई को किया जाएगा पुरस्कृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और प्रदेश के चार नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित 'स्पार्क-2023-24' पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और चारों नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा।

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है।

मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक गतिशीलता, संस्थागत विकास, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण एवं शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता के साथ ही शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने भी सूडा और पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महिलाओं एवं युवाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मिशन है। छत्तीसगढ़ इस मिशन मे लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। भारत सरकार द्वारा इन पुरस्कारों के लिए चयन हमारी कोशिशों की सफलता का घोतक है। सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नगरीय निकायों ने शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है। राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा

रायपुर। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने इन शिविरो में नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि आमजन की भागीदारी में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को जरुरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगरीय निकायों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आमजनों की भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति इन शिविरों में जरुर देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद आज राज्य शासन द्वारा सभी नगरीय निकायों को आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य दायित्व है। स्थानीय नागरिक समस्याएं यथा नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है। परिपत्र में कहा गया है कि नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स की मरकरी/बल्ब/ट्यूबलाइट का बंद रहना आदि समस्याएं भी हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

बलौदाबाजार हिंसाः भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने साथी के साथ किया सरेंडर

बलौदाबाजार। 10 जून को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में आगजनी और तोड़फोड मामले में पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. वहीं आज भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने अपने साथी हेमंत बंजारे के साथ सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए न्यायालय से 20 जुलाई तक रिमांड मांगा. इस पर कोर्ट ने 18 जुलाई तक पुलिस रिमांड दिया है. आरोपी की ओर से अधिवक्ता शारिक खान ने बताया कि उनके अलावा तीन अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की और उनके पक्षकार दिनेश चतुर्वेदी व हेमंत बंजारे ने मामले में संलिप्तता से इंकार करते हुए पुलिस रिमांड का विरोध किया. पुलिस ने 20 जुलाई तक रिमांड मांगा था, जिस पर हमारे विरोध के बाद 18 जुलाई तक रिमांड दिया गया है. वहीं रिमांड मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है. अब घटना को लेकर 18 जुलाई तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी.कोर्ट से निकलते हुए भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने मीडिया से कहा, पुलिस बेवजह प्रताड़ित कर रही है.

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग वाला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में अपराधिक घटनायें भयावह हो चुकी है। आम आदमी परेशान है, सरकार और पुलिस नागरिकों को सुरक्षा दे पाने में असफल साबित हो रही है। राजधानी में एक दिन पहले गोलीबारी हुई थी, अब शंकर नगर जैसे संभ्रांत इलाके में तीन बदमाशों ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को चाकूमार कर लूट लिया। राज्य के मनेन्द्रगढ़ में 10 बदमाशों ने एक नवयुवक की दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर हत्या कर दिया। दुर्भाग्यजनक है कि सरकार के मंत्री अपराधो पर लगाम लगाने पुलिसिंग का मजबूत करने के बजाय शुतुरमुर्ग वाला चरित्र दिखा रहे है। वे अपराधों को ही झुठलाने के लिये बयान देते है। मंत्रियों के इन बयानों से अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे है। मंत्रियो के इन बयानों से ऐसा लगता है कि अपराधियों को सत्तारूढ़ दल के लोगो का संरक्षण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने अभी 6 महिना नहीं हुये है प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गये है अपराधी बेलगाम हो चुके है सरेआम लोगो की हत्याएं की जा रही है गोलियां चल रही है। प्रदेश में एक बार फिर वहीं आतंक का दौर वापस आ गया है.

शहर से कचरे का उठाव तुरंत करें- कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह

रायपुर। नगर निगम सभी जोन में किसी भी स्थिति में कचरे का जमाव न होने दें। यह पाया जा रहा है कि कूड़े का देरी से उठाव होने से जगह-जगह गंदगी पसरी हुई है, इससे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। निगम का अमला रिस्पॉंस टाईम में कचरे का उठाव करें। यह निर्देश कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने समय-सीमा की बैठक में सभी जोन कमिश्नरों को दी। उन्होंने कहा कि कंडम गाड़ियों के कारण सड़कों में, गलियों में यातायात बाधित हो रहा है। नगर निगम और पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर इन्हें हटाएं और कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा डीकेएस, मेकाहारा तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल-कॉलेजों के बाहर अवैध रूप से ठेलें-खोमचें का कब्जा हुआ है। जिससे इन स्थानों आवाजाही में बाधा और अन्य शिकायतें आ रही है। सड़कों के किनारे कबाड़ और कंडम गाड़ियों सहित यातायात बाधित हो रहें है। पुलिस विभाग, नगर निगम ऐसे मामलों पर समय-समय पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन में कब्जा और अतिक्रमण जैसी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें।

निलंबित आरक्षक सहदेव यादव बर्खास्त

दुर्ग. महादेव सट्टा एप मामले में चार दिन पहले गिरफ्तार आरक्षक सहदेव सिंह यादव को दुर्ग एसपी ने बर्खास्त कर दिया है. बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे आरक्षक को पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के केमक ढाबे से गिरफ्तार किया था. बता दें कि जवान सहदेव को इससे पहले निलंबित किया जा चुका था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था. एसपी की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि अपनी ड्यूटी से 127 दिन अनुपस्थित रहने व पुलिस रेग्युलेशन और एमपी/सीजी सिविल सेवा आचरण नियम विरुद्ध आचरण करने, बिना विभागीय अनुमति के अपने बैंक खाते में धनराशि रखने जैसे गंभीर आरोपों के बाद विभागीय जांच के आधार पर आरक्षक सहदेव यादव को बर्खास्त किया गया है.बता दें कि आरोपी सहदेव यादव के कब्जे से 11 बैंक खातों में जमा दो करोड़ रुपये को फ्रीज किया गया है. साथ ही एसीबी ने सट्टे के पैसे से खरीदी गई इनोवा को भी जब्त किया है. सहदेव के दो भाई भीम यादव और अर्जुन यादव पहले से जेल में बंद हैं. तीनों भाई पुलिस विभाग में होकर ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे थे.

शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैः कश्यप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव जोर-शोर से चल रहा है। स्कूलों में नव प्रवेशी बच्चों को फूल-मालाओं से स्वागत के साथ ही उनका मुंह मीठा कराकर प्रवेश कराया जा रहा है। इसी कड़ी में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी जिला मुख्यालय सुकमा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शिक्षा ही समाज में बदलाव का माध्यम है। शिक्षा से ही हम अपने भविष्य को तराश सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने नव प्रवेशी बच्चों को फूल, माला और तिलक लगाकर शाला में प्रवेश दिलाया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप शाला प्रवेश उत्सव को सम्बोधित करते हुए कहा कि आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थान हमारे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है.

आई.जी.के.वी., एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सी.आई.ए.टी के बीच हुआ समझौता

छत्तीसगढ़ की विलुप्तप्राय परंपरागत फसल प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की परंपरागत विशेषकर विलुप्तप्राय फसल प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थित में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सी.आई.ए.टी. के मध्य संपादित अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में विभिन्न फसलों की परंपरागत देसी किस्मां विशेषकर चावल की विलुप्त हो रही देसी किस्मों का संरक्षण तथा विकास करना है। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गां में व्याप्त कुपोषण को दूर करना तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना भी है। इन तीनों संस्थाओं के मध्य विगत दस वर्षां से संचालित परियोजना को आगामी दस वर्षों तक बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल तथा एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल के भारत के प्रतिनिधि डॉ. जे.सी. राणा ने हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के तहत विगत दस वर्षां में कोरिया, सरगुजा तथा धमतरी जिलों में तीन सामुदायिक बीज बैंक स्थापित किये गये हैं, धान की जीरा फूल और नगरी दुबराज प्रजातियों को जी.आई. टैग प्राप्त हुआ है तथा विभिन्न फसलों की अनेक विलुप्तप्राय परंपरागत किस्मों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु प्रयास किये गये हैं।

बैठक में कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने राज्य की कृषि जैव विविधता पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच जैव विविधता से जुड़े ज्ञान का आदान-प्रदान करना है, और जैव विविधता से विकसित उत्पादों का प्रसार और व्यावसायीकरण करना है। एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी के कंट्री हेड डॉ. जेसी राणा ने जोर दिया कि मौजूदा औपचारिक बीज प्रणाली के साथ किसानों के खेत और उपभोक्ताओं के बीच मौजूदा अंतर को भरने के लिए विभिन्न फसलों की पहचान की गई है और संभावित भूमि प्रजातियों के बाजार लिंकेज पर अधिक प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि पारंपरिक किस्मों की पोषण संबंधी रूपरेखा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। पोषण संबंधी प्रोफाइलिंग डेटा को इन पारंपरिक भूमि प्रजातियों के प्रचलित स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान (आईटीके) के साथ जोड़ने से इन आईटीके को वैज्ञानिक मान्यता मिलेगी। एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सी.आई.ए.टी. एशिया के प्रबंध निदेशक डॉ. स्ट्रेफन वाइस ने अपने संबोधन में आईजीकेवी को पिछले प्रोजेक्ट्स के आशाजनक परिणामों के लिए बधाई दी और कहा कि यह नया समझौता ज्ञापन स्थायी संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन और कृषि जैव विविधता के प्रबंधन पर अनुसंधान और विकास की ओर अधिक निर्देशित होगा, फसल प्रजातियों पर जानकारी तक पहुंच में सुधार के लिए और फसल आनुवंशिक और प्रजनन कार्यक्रम विकसित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे। कर्मचारियों के आदान-प्रदान, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. अजय वर्मा, निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, रायपुर डॉ. जी.के. दास, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, अधिष्ठाता खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर डॉ. ए.के. दवे, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा सहित वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.